विदर्भ में हाशिए का समाज और मीडिया

(विशेष संदर्भ: दैनिक भास्कर और लोकमत समाचार)

Marginalize Society in Vidarbha and Media

Special Reference: Dainik Bhaskar and Lokmat News paper

जनसंचार विषय में एम.फिल.उपाधि के लिए प्रस्तुत

लधु शोध प्रबंध

सत्र 2015-16

शोधार्थी

विकास कुमार

2014/05/208/002

संचार एवं मीडिया अध्ययन केन्द्र

(मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ)

महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी गाँधी हिल्स , वर्धा-442005 (महाराष्ट्र) भारत

विदर्भ में हाशिए का समाज और मीडिया

(विशेष संदर्भ: दैनिक भास्कर और लोकमत समाचारपत्र)

1घोषणा पत्र

2 प्रमाण पत्र

3 आभार

विषय प्रवेश

(क) शोध समस्या का परिचय 7

(ख) शोध का महत्व एवं प्रसांगिकता

(ग) शोध प्रविधि

(घ) शोध की सीमाएँ

(ण) साहित्य पुनरावलोकन 15

अध्याय 1

1 हाशिए के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 16

(क) हाशिए के समाज का परिचय

(ख) वर्चस्ववादी समाज में हाशिए के लोग/ हाशिए के समाज की स्थिति 25

अध्याय 2

2 राष्ट्रीय विकास में हाशिए के समाज का योगदान 26

(क) दलित वर्ग

(ख) आदिवासी वर्ग

(ग) अल्पसंख्यक वर्ग 32

अध्याय 3

1 मीडिया का सामाजिक सरोकार 33

(क) दलित

(ख) आदिवासी

(ग) अल्पसंख्यक 38

अध्याय 4

1 हाशिए का समाज: मीडिया दृष्टि और समाजिक स्थिति 39

(क) सामाजिक

(ख) आर्थिक

(ग) राजनीतिक 49

अध्याय 5

1 चयनित मीडिया का विश्लेषण 50

- चयन का आधार
- तथ्य संकलन प्रक्रिया
- तथ्य विश्लेषण

(क) लोकमत समाचार

(ख) दैनिक भास्कर 63

निष्कर्ष एवं आवश्यक सुझाव 64-65

परिशिष्ट 66-78

संदर्भ सूची 79-8

विषय प्रवेश

हाशिए के समाज को यदि सामाजिक सरंचना के आधार पर देखा जाए तो सामाजिक सरंचना का एक स्वरूप होता है जिसे देखा व परखा जा सकता है। *हर्बट स्पेंसर*ने सामाजिक सरंचना की तुलना मानव शरीर से की, उनका कहना था कि "जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और वे सभी शारीरिक बनावट को बनाये रखते हैं उसी प्रकार समाज के भी विभिन्न अंग होते हैं जो समाज के बनावट को बनाये रखते हैं। सामाजिक सरंचना से हमारा अभिप्राय एक व्यवस्था से होता है जिसमें उस व्यवस्था व सरंचना के विभिन्न तत्व एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। तत्वों के इस समीकरण और व्यवस्थित पद्धति को ही सरंचना कहा जा सकता है" व्यक्ति सामाजिक सरंचना में एक स्थान पर रहते हैं उनका एक व्यवस्था में स्थान ग्रहण करना एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत होता है जिसके अंतर्गत कुछ प्रतिमानों के कारण उन्हें वह स्थान मिला होता है। इस प्रकार सामाजिक सरंचना व्यक्ति का एक व्यवस्थित रूप है जिसमें उनके सामाजिक संबंध किसी खास संस्थात्मक मूल्यों से नियंत्रित होते हैं। अगर हम परिवार के बनावट की बात करें तो उस परिवार के सदस्य की एक खास भूमिका होती है। इस प्रकार एक संगठन में सभी व्यक्तियों को अपनी-अपनी भूमिका अदा करने के लिए एक-दूसरे से जुड़ा होना आवश्यक है।

सामाजिक संरचना को और समझने के लिए उस समाज के मूल्यों का तथा उसके संस्थात्मक स्वरूप को समझना आवश्यक है। *टालकाट पारसंस* के अनुसार "किसी भी सामाजिक व्यवस्था को चार प्रमुख सामाजिक कार्य स्थायी रूप से करने पड़ते हैं-

(क) अनुकूलन: इसके अनुसार भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है।

(ख) लक्ष्य उपलब्धि: समाज में व्यक्ति व समूह के बीच लक्ष्य निर्धारित करना तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना सम्मिलित होता है।

(ग) प्रतिमान अनुरक्षण: कार्यों को संपादित करने के लिए उत्साहवर्धन करना।

(घ) एकीकरण: आंतरिक सम्बन्ध स्थापित कर एकीकृत करना भी उस समाज का कर्त्तव्य हो जाता है।

> **यदि वर्ग की बात की जाये तो** मार्क्स ने दो मूलभूत वर्ग का विभाजन किया है 'बुर्जुआ' और 'सर्वहारा',उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के पास हैं, लेकिन इसमें प्रभावी रूप से सर्वहारा वर्ग शामिल हैं क्योंकि केवल वे अपनी श्रम शक्ति बेचने में सक्षम हैं।[1]

[1]https://hi.wikipedia.org/wiki/सामाजिक संरचना

समकालीन समय में हम कह सकते हैं कि वर्चस्व का इतिहास उतना ही पुराना है जितना जीव का वर्चस्व की इस लड़ाई में हमेशा से ही ऐसा होता आया है कि एक वर्ग सत्ता के केंद्र में आया है तो दूसरा हाशिए पर ढकेल दिया गया है। सामाजिक रचनाओं पर गौर करें तो हमें वे संरचनाएँ बड़ी आसानी से दिख जाती हैं जो किसी वर्ग विशेष को हाशिए की ओर ढकेलती हैं। इन वर्गों की अपेक्षा और उत्पीड़न का एक बड़ा कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक होता है उससे भी ज्यादा इसका सरोकार इस बात से होता है कि वे वर्ग विशेष अपने आपको किस संदर्भ में, किन तरीकों के साथ अभिव्यक्त करते हैं। हाशिए के समाज के संदर्भ में उत्पीड़न की अवस्था को समझने के लिए हमारे पास जो विमर्श की तकनीक है वह पर्याप्त नहीं है। यह तकनीक 'सामाजिक जड़ता'से पूरी तरह नियंत्रित होती है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं कि विमर्श के इस अधूरेपन को समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त अवसर है या नहीं सवाल यह भी है कि हम उन अवसरों को मुहैया कराने की कोशिश भी कर रहे हैं या नहीं ?[2]

जब हम मीडिया विषय का अध्ययन करते, चर्चा, संगोष्ठियों में शामिल होते हैं तो मुझे लगता कि मीडिया में हाशिए समाज की संख्या न के बराबर है ऐसा क्यों? आखिर हाशिए का समाज किसको कहेंगे मीडिया में हाशिए के समाज कि कितनी उपस्थिति है। इन्हीं सवालों के उत्तर तलाशने के लिए इस विषय का चुनाव किया गया।

शोध समस्या का परिचय

समकालीन दौर में मीडिया स्वरूप के व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं तथा मीडिया को एक लोकतंत्र का चौथा आधार स्तभ माना गया है लोकतंत्र लोगों के लिए समानता, स्वतंत्रता और वन्धुत्व की बात करता है लेकिन यह समानता मीडिया के क्षेत्र में बहुत कम दिखाई पड़ती है आज भी मीडिया में उच्च वर्ग का वर्चस्व है, ऐसा क्यों? यदि कोई दलित मीडिया से जुड़ना चाहता है तो मीडिया उसे जानबूझ कर नहीं अपनाना चाहती है। यदि कोई दलित मीडिया में प्रवेश करता है तो उसे शीर्ष तक पहुंचने नहीं दिया जाता बल्कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है. क्या भारतीय मीडिया का यही स्वरूप है?

जिस समानता, बन्धुत्व, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को लेकर मीडिया का विकास हुआ आज वही मीडिया समाज के वंचित, उपेक्षित तथा हाशिए के समाज के प्रति क्यों नहीं आवाज उठा पा रही है? मीडिया से दलितों की समस्यायें क्यों गायब हो गई दलित संबंधी मुद्दो को इतनी प्रखरता से क्यों नहीं उठाया जाता साथ-साथ कोई खबर मीडिया में आती भी है तो उसे उतनी वरीयता नहीं मिल पाती जितनी अन्य मसालेदार खबरों को दी जाती है, इस शोध के माध्यम से दलितों के प्रति मीडिया की उपेक्षा,

---

[2]अजय कुमार सिंह,मीडिया इतिहास और हाशिए के लोग,(हरियाणा:आधार प्रकाशन एस.सी.एफ.26,सेक्टर 16 पंचकुला 134113 प्रकाशन वर्ष 2007) पृष्ठ संख्या 12

मीडिया के कर्तव्य एवं अधिकार हाशिए के समाज के लोगों की स्थिति उनकी समस्याओं एवं शिकायत जैसे- उद्देश्यों को भी बाहर लाने का प्रयास किया जायेगा।

शोध का महत्व एवं प्रासंगिक्ता

शोध कार्य बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के नहीं होता है, इस उद्देश्य या लक्ष्य का विकास और स्पष्टीकरण शोध कार्य के दौरान नहीं होता, अपितु वास्तविक अध्ययन प्रारम्भ होने से पूर्व ही इसका निर्धारण कर लिया जाता है। अतः शोध अद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने के लिए पहले से बनाई गई योजना की रूप रेखा को शोध-प्ररचना या अभिकल्प कहते हैं। मैंने ''हाशिए का समाज और मीडिया'' शोध कार्य में यह दिखाने का प्रयास किया है कि हाशिए के समाज को मीडिया किस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है। जिससे हाशिए के समाज को एक नयी दिशा मिले तथा ऐसा समाज जो दलित दमित तथा शोषित है उन पर सरकार तथा मीडिया कितना ध्यान दे पा रही है या नहीं? हाशिए के समाज की उपस्थिति मीडिया में न के बराबर है इस प्रश्न को जानने के लिए शोध की प्रासंगिक्ता और भी बढ़ जाती है।

1हाशिए के समाज के उत्थान एवं पतन में पूंजीवादी वर्चस्व और प्रिंट मीडिया के योगदान का अध्ययन करना।

2 आधुनिक समय में हाशिए के समाज के लोगो के प्रति मीडिया में परिस्थिति का अध्ययन करना।

3 उपेक्षित वर्गों के प्रति क्या मीडिया अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को निभाने में सक्षम भूमिका अदा कर रहा है, का अध्ययन।

4 हाशिए के समाज के प्रति मीडिया की भूमिका का अध्ययन करना साथ ही मीडिया द्वारा किये गये प्रयाशों के कारण इन समाजों में पढ़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध का आधार उपागम विश्लेषणात्मक प्रविधि से किया गया है। जिसमे में मात्रात्मक एवं गुणात्मक शोध माध्यम का प्रयोग किया गया इसके अंतर्गत आकड़ों के प्राथमिक स्रोत के रूप में दैनिक भास्कर, लोकमत समाचारपत्र को लिया गया। साथ-साथ तथ्य संकलन के लिए साक्षात्कार, चर्चा, संगोष्ठी, निरीक्षण इत्यादि प्रविधियों का प्रयोग किया गया। द्वितीयक स्रोतों के रूप मे पुस्तकें,पत्रिकाएँ ,शोध आलेख एवं इंटरनेट सामग्री का प्रयोग किया गया है।

प्रमाणिकता एवं व्यावहारिक्ता के लिए दैनिक भास्कर एवं लोकमत समाचारपत्र में हाशिए के समाज के लोगों की स्थिति का अध्ययन उपस्थित खबरों से विश्लेषण किया गया। तथा दोनो संपादकों का

साक्षात्कार भी किया गया। हर पृष्ठ पर जहां संदर्भ का प्रयोग किया गया। तथा फुटनोट का प्रयोग किया गया। एंडनोट का नहीं संदर्भ लेखन के लिए अमेरिकन साइक्लोजी इंडेक्स का प्रयोग किया गया है।

शोध की सीमाएँ

शोध की सीमा नागपुर से प्रकाशित दैनिक भास्कर और लोकमत समाचारपत्र के विदर्भ क्षेत्र पृष्ठों पर आधारित है। तथा दोनो समाचार पत्र की अवधि 1 जनवरी 2015 से 31 जनवरी 2015 तक ही रखी गयी है जिसमें हाशिए के समाज की उन सभी घटनाओं को समाचार-पत्रों में ख़गालने का प्रयास किया गया है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुददों से अलग है। हाशिए समाज को एक सीमा में बांध कर शोध किया गया जिसमें हाशिए के समाज में उन वर्गो को रखा गया जो दलित, आदिवासी तथा अल्पसंख्यक हैं।

साहित्य पुनरावलोकन

1 सिंह अजय कुमार, मीडिया इतिहास और हाशिए के लोग. हरियाणा:आधार प्रकाशन पंचकूला-134 113, 2007

इस पुस्तक में लेखक ने कहा है कि- मीडिया का व्यवस्थित अध्ययन अपेक्षाकृत काफी नया मामला है बावजूद इसके हम बीसवीं सदी के लगभग तमाम समाजशास्त्री विमर्शों में मीडिया की चारित्रिक विशेषता पर चर्चा बीसवीं सदी के कई बड़े समाजशास्त्रियों ने की है। इन अध्ययनों में इसको कई बार सम्प्रेषण के साधनों के तौर पर व्याख्यापित करने की कोशिश की गई तो कई बार उन्होंने इसे ही विमर्श का औजार समझा।

इस पुस्तक के दो मुख्य हिस्से हैं। पहले हिस्से में विभिन्न घटनाओं के जरिये मीडिया की प्रकृति का रेखांकन किया गया है यह हिस्सा मुख्य तौर पर उत्तर-औपनिवेशिक काल में हाशिए के समाज और भारतीय मीडिया के बीच के सम्बन्ध पर आधारित है। तथा दूसरे हिस्से में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों पर हुए विवाद पर मीडिया द्वारा अपनाये गये रवैये का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2 जोशी रामशरण, मीडिया-विमर्श.नई दिल्ली:सामयिक प्रकाशन 3320-21 जटवाड़ा,नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, 110002

इस पुस्तक में लेखक कहता है कि- मीडिया विमर्श में राजनीतिक रूप से 1977 में जनता पार्टी के शासन काल से लेकर 1980 में इंदिरा वापसी और 1984 में राजीव के उदय तक हिंदी पत्रकारिता में एक नई धारा का उफान दिखाई देता है। इस दौर में क्षेत्रीय पत्रकारिता एक ताकत के रूप में उभरती है। हिंदी राज्यों में क्षेत्रीय अखबारों का विस्तार होता है। इसी दौर में नई क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां भी सामने

आतीं हैं। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं छलांगें लगातीं हैं। एकाधिकार पूंजीपति वर्ग के समांतर क्षेत्रीय स्तर पर पूंजीपति वर्ग तेजी से सामने आता है।

इस दौर में मिशनरी पत्रकारिता का युग बिलकुल समाप्त हो गया है। इसका स्थान संपूर्ण व्यावसायिकता ने ले लिया। पत्रकारिता को नई गति भी मिली। राजनीतिक घटनाचक्र में जितनी तीव्रता आई, पत्रकारिता ने भी वैसे ही व्यावसायिक गतिशीलता का परिचय दिया। हिंदी पत्रकारिता में पूंजी विस्तार ने व्यावसायिकता को जरूर जन्म दिया। इसने उसकी देह को चमकीला-भड़कीला जरूर बना दिया, लेकिन उसकी आत्मा खोखली होती चली गई। इसकी वजह यह भी थी कि क्षेत्रीय पत्र-पत्रिकाओं के मालिक मूलत महाजनी पूंजीपति थे। उन्होंने पूंजी अर्जित की, उसे नियोजन किया, लेकिन वे अपने व्यावसायिक व्यवहार में बुनियादी बदलाव नहीं ला सके।

3 कुमार संजय, मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओगे.नई दिल्ली: प्रकाशक सम्यक प्रकाशन 32-3, पश्चिमपुरी, 110063,

इस पुस्तक में लेखक कहता है कि मीडिया के लिए आज के समय में खतरा केवल सत्ता की ओर से नहीं आता बल्कि वह उसके अंदर से भी आता है। व्यवसाय में तबदील मीडिया पर जातिवाद, भाई-भतीजावाद आदि के आरोप भी लगते रहे हैं। मीडिया के जाति प्रेम का खुलासा, सर्वे रिपोर्टिंग से हो चुका है। यानी मीडिया में दलितों की हिस्सेदारी नहीं है। भारतीय मीडिया में दलितों के सवालों के प्रवेश पर अघोषित प्रतिबंध को किताब बेनकाब करती है। ''मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओगे'' में सप्रमाण यह सिद्ध किया गया है कि मीडिया हाउसों पर ऊंचें पदों पर सवर्ण ही आसीन है और उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रच रखा है कि किसी दलित का या तो वहां पहुंच पाना ही असंभव होता है। अगर किसी तरह पहुँच भी गया तो, टिक पाना मुश्किल है। मीडिया में सत्य और तथ्य में बहुत बड़ा अंतर है और अक्सर तथ्य सत्य को छुपा जाता है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो मीडिया का रूप है वह किसी सामाजिक तथा हाशिए के लोगों को उठाना नहीं बल्कि उनको नीचे ही रहने को अग्रसर करता है। मीडिया को अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ कर आगे आने का प्रयास करना होगा।

4 सुमन हंसराज,मीडिया और दलित.नई दिल्ली:प्रकाशन श्री नटराज प्रकाशन 4378/4 बी, 306,जे एन.डी, हाऊस, अंसारी रोड,दरियागंज,110002,2009

इस पुस्तक में उन सभी पहलुओं को दिखाने का प्रयास किया गया है जो मीडिया और दलित के बीच में बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी खाई है इन खाईयों को प्रस्तुत किया गया है इस पुस्तक में बताया गया है कि आजादी के 61 साल हो चुके हैं। भारतीय मीडिया ने नये-नये स्वरूप देखने को मिल रहें हैं। पर भारतीय मीडिया दलितों को आज भी मुख्य धारा से अलग रखे हुए हैं। इसकी मानसिकता आज भी

दलितों को अपेक्षित व हेय दृष्टि से देखता है तथा दलित उत्पीड़न की खबरों की जितनी प्रमुखता से छापा जाता है उतनी उसके विकास की खबरों को महत्व नहीं दिया जाता है।

इसके अलावा दलितों को मुख्य धारा की मीडिया में भागीदारी के सवाल को लेकर पाठकों के समक्ष विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में वरिष्ठ लेखक, पत्रकार,साहित्यकारों के दलित पत्रकारिता के संबंध में विचार संकलित है ताकि शोधार्थियों व गैर दलितों को दलित पत्रकारिता पर सोचने के लिये वाध्य करें। लेखक डॉ. योगेन्द्र यादव, राजदीप सरदेसाई, अनिल चमड़िया, डॉ. आनंद प्रधान, प्रो. विवेक कुमार, के. पी. सिंह, कांशीराम, वीर भारत तलवार, एच.एल. दुसाध आदि लेखकों ने विस्तार से विवेचन किया है।

5 फैसल हरिवंश, जन सरोकार की पत्रकारिता.नई दिल्ली:अनुरागप्रकाशन 4715/21 दयानंद मार्ग, दरियागंज, 110002, 2009

इस पुस्तक में सम्पादक ने अंग्रेज शासकों और उनके सूवेदारों सामंतों के आतंक से 1857 का विद्रोह विखर चुका था। उन्हीं दिनों 1888 के लगभग जतरा भगत का जन्म हुआ। आदिवासी के पांच महापुरूष और थे जिन्हें सिदो, कान्हू, बुद्ध, बिरसा और जतरा। उन दिनों अंग्रेज साहबों और उनके कारिंदे सामंतों के लिए नेतरहाट की पाहाड़ियों को सुंदर बना रहे थे। उस समय लोगों के जुबान पर एक ही नारा था ‘‘चिंगारी नू धरती धरमे’’ क्योंकि जतरा का जन्म चिंगरी नामक गांव में हुआ था इसीलिए चिंगरी गांव के लिए सारे आदिवासी उमड़ पड़े जहां जतरा भगत ने अह्वान किया। बाहरी सभ्यता-संस्कृति और आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ यह पहला स्वदेशी विद्रोह था।

6 नैमिशराय मोहनदास, दलित पत्रकारिता.नई दिल्ली:प्रकाशन श्री नटराज ए 507/12 करतार नगर, बाबा श्यामगिरी मार्ग 110053, 2008

इस पुस्तक में लेखक कहता है कि- साठ वर्ष की आजादी के बाद दलित समाज के अधिकांश लोग हाशिए पर रहे हैं सही मायने में यदि देखा जाये तो सवाल, साहित्य य पत्रकारिता भी हाशिए पर रही है स्वर्ण समाज के कुछ लेखक व पत्रकार अपनी कलम दलितों पर चलाते आये हैं। स्वर्ण पत्रकारों ने दलित पत्रकारिता के बहाने नकारात्मक रवैया अपनाया। मनुष्यों के विचारों को पत्रकारिता इधर से उधर अदिकाल से ढोती हुई एक सेतु का काम करती रही है। एक तरफ हम कह सकते हैं कि बदलाव तो हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए था उतना बदलाव नहीं हुआ है आज भी भारतीय समाज में ऊंच-नीच, गरीबी-अमीरी बरकरार समता मूलक समाज बनाने के उद्देश्य से हिंदी पत्रकारिता में दलित सवालों को बड़ी बेबाकी से उठाते रहें है। जहां उन्होंने दोहरी सवर्ण मानसिकता को उजागर किया वही दलितों में उग रहे ब्राह्मणवादी तेवर को भी बड़ी शिद्दत के साथ अपने लेखों से प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में लेखक ने सामाजिक सांस्कृतिक, साहित्यक व राजनीतिक विषयों को उजागर करने का प्रयास किया है।

7 गौतम रूपचन्द्र, दलित रिपोर्टिंग.दिल्ली: प्रकाशन-ए-507/12,साउथ गांवडी एक्सटेंशन 110053, 2007

लेखक ने अपनी पेन्सिल दलित रिपोर्टिंग पत्रकारिता की ओर चलाई. पत्रकार का समाज से जितना गहरा संबंध होगा वह उतनी ही सटीक रिपोर्टिंग कर सकता है। गौतम जी ने दलित आन्दोलन से काफी समय से जुड़े हुए हैं। इन्होंने विशेष कर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग की है। इन्हें पढ़ने से सचमुच में दलित आन्दोलन ताजा होता है। दलित साहित्य में 'दलित रिपोर्टिंग' पर एक मात्र पुस्तक है। लेखक का मानना है कि जब घटना घटती है तब विश्लेषण जरूरी है। पत्रकारिता से जुडा विश्लेषण ही पत्रकारिता का सामाजिक सरोकार बन जाता है। समाज के कार्यक्रम ही ऊर्जा के स्रोत होते हैं। पीड़ा के बाद चिंतन और आलेख तैयार होता है। यह सब लेखक अपने अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत करते है क्योंकि कि आन्दोलन से उनका गहरा रिश्ता रहा है। लेखक ने आंकड़े प्रस्तुत करके लेखों की प्रामाणिक्ता को बढ़ाया है। अन्त में गौतम जी का मानना है कि यह पुस्तक पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान प्रदान करेगी तथा पत्रकारिता से जुड़े लोगों को एक नई दिशा प्रदान होगी।

8 मल्होत्रा महेन्द्र, मीडिया के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सरोकार. नई दिल्ली:प्रकाशन-रावत 4264/3, अंसारी रोड, दरियागंज -110002, 2012

लेखक ने मीडिया के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सरोकार पर हम सभी का ध्यान अर्जित किया है जिसमें उन्होंने बहुत ही बारीकी से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं पर अपनी बात रखी। मल्होत्रा जी का कहना है कि मीडिया अपने वाल्यवस्था से ही सामाजिक दायित्यों का निर्वहन करती आ रही है। मीडिया ने हमेशा से ही सामाजिक समस्याओं को जनमानस तक पहुँचाकर उसे दूर करने के लिए लोगों को उठने की प्रेरणा दी है। मीडिया के इन तीनों पहलुओं को हमने आपने शोध पत्र में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जो वर्तमान समय में सत्य भी है जिन पर मीडिया का पूरा जीवन टिका हुआ है। लेखक का यह भी मानना है। कि पत्रकारिता का जन्म तो कलकत्ता में हुआ लेकिन उसका लालन-पालन मुंबई में हुआ। भारतीय पत्रकारिता ने कृष्णदास मुलजी, गोपाल राव हरि देशमुख, बहराम, दादाभाई नौरोजी जैसे सामाज सेवकों के सहयोग से एक नई ऊँचाई को पाई। विद्रोह के एक वर्ष पहले और इसके कई वर्ष पश्चात भी समाज सुधार मुंबई के भाषा प्रेस का मुख्य विषय बना रहा।

9 परिहार डॉ.एस.एल, दलितों को अनपढ़ रखने की साजिश.जयपुर:प्रकाशन-बुद्धम् पब्लिशर्स 21-ए, धर्मपार्क,श्याम नगर11 अजमेर रोड़ -302019 राजस्थान, 2014

डॉ .एस.एल.परिहार ने शोषितों के खिलाफ मौजूदा शिक्षा नीतियों की असलियत को उजागर करने का प्रयास किया है। साथ में डॉ. ने यह भी कहा कि किसी देवी देवताओं के सामने अपनी नाक मत रगडो, भाग्य किसी व्यक्ति या देवी के बनाने से नहीं बनता अपना भाग्य आप खुद बनाओ तुम्हारी मुक्ति का मार्ग धर्मशास्त्र व मंदिर नहीं है बल्कि तुम्हारा उद्धार उच्च शिक्षा व्यवसायी बनाने वाले रोजगार तथा उच्च आचरण व नैतिकता में निहित है। तीर्थयात्रा या कर्म-कांर्ड में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। गरीबी से मुक्ति नहीं दिलाएगी। धर्म मनुष्य के लिए है। मनुष्य धर्म के लिए नहीं और जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता व धर्म नहीं अधर्म का बोझ है जहां ऊँच और नीच की व्यवस्था है। वह धर्म नहीं, गुलाम बनाये रखने की साजिश है।

10 परिहार कालूराम,मीडिया के सामाजिक सरोकार.नई दिल्ली:प्रकाशन अनामिका प्रब्लिशर्स एंडडिस्ट्री ब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड अंसारी रोड़ दरियागंज110002, 2008

यह पुस्तक मीडिया की भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में अभिव्यक्त की जाने वाली चिताओं को केंद्र में रखकर लिखी गई आलोचानात्मक पुस्तक है। लेखक ने मीडिया के सामाजिक प्रभाव को रेखांकित करते हुए उसकी गतिविधियों को गहराई से विश्लेषण किया है। समाज में यथास्थिति और नियंत्रण बनाए रखने के लिए सामाजिक शक्तिओं द्वारा मीडिया का भरपूर उपयोग किया गया है। लेखक का यह भी मत है कि समाज में परिवर्तन लाने की पूरी शक्ति और संभावना मीडिया में है लेकिन केवल मीडिया पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता क्योंकि सामाजिक विकास में अनेक बाधाएँ है जो मीडिया की पहुंच और दखल से बाहर है।

पुस्तक में इस बात पर सूक्ष्मता से विचार किया गया है कि किस तरह हाल के वर्षों मे सूचना और संचार-क्षेत्र का औद्योगिक और आर्थिक महत्व बढ़ने से मीडिया व्यापार बन गया है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से बाजारोन्मुख होकर मीडिया ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। साथ में यह भी बताया गया कि मीडिया के पूंजीवाद को बढ़ाता है और पूंजीवादी मीडिया का पोषण करता है यह बात सही है। मीडिया अपने किसी भी रूप में अंततः एक मानवीय और संचालन करते है तो लोग उसे बदल भी सकते हैं। यद्यपि मीडिया ऐसी जबर्दस्त संस्था है कि जो सामान्य व्यक्ति के नियंत्रण और हस्तक्षेप से परे हैं।

11 काजल डॉ.अजमे सिंह, दलित चिंतन के आयाम.दिल्ली:प्रकाशन ए-507/12 साउथ गामड़ी एक्स 110053, 2012

दलित चिंतन के आयाम में चिंतन के उन रूपों को अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया गया है। जो आधुनिक समाज निर्माण के लिए अनिवार्य है इनकी अनिवार्यता सार्वभौमिक न्याय और समता मूलक समाज की रचना के लिए है। यदि स्थापित व्यवहारों को देखा जाए तो व्यवस्था पर सामाजिक रूप से आधिपत्य प्राप्त वर्ग की सभी क्षेत्रों में अधिक हैं। देश की समुचित सत्ताएं इनके हिसाब से कार्य करती हैं। यदि कोई इनके इशारों से हटकर अन्य व्यवहारों को अपनाने के प्रयास करे तो उसे सत्ता से ही निकाल दिया जाता है। यदि सही मायने में देखा जाये तो अल्प आबादी के पास साधन और संसाधनों, जीवन-यापन की भारी कमी है। असल में सत्ताओं ने प्रतिनिधित्व के सवालों के माध्यम से अपना ही हित साधा है। दलित चिंतन इन्हीं प्रश्नों को बार-बार उठाकर जनता और समाज को संघर्ष चेतना के लिए तैयार करता है।

दलित चिंतन ने साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक परिवेश को गहराई से प्रभावित किया है। दलित चिंतन स्वभाव से दलित नहीं बल्कि न्याय के पक्ष से परिवर्तनकारी है। और इसका वह रूप सभी क्षेत्रों में बिखर चुका है। यह पुस्तक न्याय, अस्मिता, प्रतिनिधित्व और समता के मूलभूत प्रश्नों को उठाती है और समाज को न्यायपरक जद्दोजहद के लिए तैयार करती है।

12 टाकभौर डॉ.सुशीला, हाशिए का विमर्श. दिल्ली: नेहा प्रकाशन 295, बैंक इक्लेब, लक्ष्मी नगर 110092, 2015

लेखक ने समाज की युवा और युवतियों में नयापन लाने एवं जिज्ञासा बढ़ाने के लिए इस पुस्तक को लिखा है। उनका कहना है कि यदि उनको एक नई दिशा मिल जाये तो शायद कुछ नया कर सकेगें। दलित समाज, दलित साहित्य और नारी से संबंधित अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। सुशीला जी ने अपनी कलम से सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ कर ही इस पुस्तक को प्रकाशित की है साथ-साथ लेखक ने इस पुस्तक में परिवर्तन, अछूत, सामाजिक क्रांति, वर्ण व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से वर्णन किया है।

13 सिंह डॉ.राम गोपाल, सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष. जयपुर प्रकाशन राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी प्लाट न. 1 झालाना सांस्थानिक क्षेत्र-302004, 2010

भारत में सामाजिक न्याय एवं विकास संबंधि लक्ष्यों की प्राप्ति का मार्ग संवैधानिक सुधार के माध्यम से खुला रखा गया है।

लेखक ने अपनी पुस्तक में भारत के सामाजिक न्याय के ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विकास-क्रम को रेखांकित करती है। यह रेखांकन सामाजिक न्याय के लिए दलित, पीडित एवं शोषित वर्ग द्वारा किये

गये संघर्ष को केंद्र में रख कर किया गया है। साथ ही न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में डॉ. अम्बेड़कर एवं गांधी के अव दानों पर भी प्रकाश डाला गया है।

अध्याय 1

हाशिए के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

निष्कर्ष

हाशिए का समाज हो या कोई अन्य समाज सभी के लिए जनमत निर्माण में सबसे अधिक प्रेस एवं समाचार-पत्र की भूमिका रहती है। आधुनिक युग में जनमत को प्रभावित करने में प्रेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रेस के माध्यम से समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, पर्चे, इत्यादि छपवा कर प्रचार-प्रसार के लिये जनता तक पहुंचाए जाते हैं। हालांकि प्रेस द्वारा अन्य चीज़ें भी छापी जाती हैं। किन्तु इन सभी में समाचार-पत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। समाचार-पत्र में कृषि, खेल, मनोरंजन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एवं सांस्कृतिक आदि सभी पहलुओं से जुड़े समाचार छपते हैं। इतना ही नहीं समाचार-पत्र के माध्यम से राष्ट्र के नेताओं के विचार भी जनता तक पहुंचते हैं। इसलिए यह आवश्यक होता है कि समाचार-पत्र निष्पक्ष होकर समाचारों को छापें अर्थात् अपनी शक्ति का उपयोग सकारात्मक रूप में करें। इस प्रकार यह पता चलता है कि प्रेस एवं समाचार-पत्र जनमत का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

आधुनिक समय में मीडिया भी अपनी मनमानी कर रही है। शोध के दौरान एक माह के समाचार पत्र को हाशिए के समाज से जुड़ी खबरों को खंगाल कर देखा तो पाया कि 31 दिनों के समाचार पत्र में 186 पेजों की लम्बाई गुणा चौड़ाई 341496cm में से लोकमत समाचार पत्र ने कुल 2.01% स्थान दिया है। इसी प्रकार से दैनिक भास्कर ने 341496cm में से कुल 1.68% ही स्थान दिया है इससे यह पता चलता है कि मीडिया भी हाशिए के समाज से बहुत कम सरोकार रखती है। समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों में यह भी देखा गया है कि सबसे अधिक राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर अधिक जोर दिया गया न की शिक्षा और स्वास्थ पर। इस समाचार पत्रों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को हम देख सकते हैं प्रभाव चाहे नकरात्मक हो या सकरात्मक दोनों ही प्रकार से देखने को मिले हैं। आधुनिक समय में मीडिया अपने दायित्व को निष्पक्ष रूप से नहीं निभा पा रही है जिसके चलते हाशिए के समाज पर विभिन्न प्रकार की जटिलतायें सामने आ रहीं हैं। हाशिए का ऐसा समाज जिसे हम किसी भी रूप में देखें सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इन सभी पहलुओं से अछूता समाज हाशिए का समाज है। पूरे शोध के दौरान पाया कि आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं तथा दलित, दमित, शेषण, आदिवासिओं को किसी न किसी रूप में उच्च वर्ग के लोगों का शिकार होना पड़ता है। यदि इस शोध के तथ्यों के आधार पर यह कहा जाये कि समाचार पत्र भी बाजार के अघोषित नियंत्रण से बाहर हैं तो यह गलत होगा। विज्ञापनों का प्रभाव और बाजार की अन्योनश्रिता समाचार समूहों पर सीधे तौर पर दिखायी पड़ती है। पूंजीवादी नियमों में बाजार भले ही समुदायों के हितों के अनुरूप कोई विभेद नहीं रखता हो किंतु समाज के आर्थिक चरण में नीचे के स्थान पर हाशिये का समाज ही होता है। जिसके प्रति न तो बाजार का कोई साकारात्मक रूख है न ही बाजार इसके लिए गंभीर है। समाचारपत्र अपनी नैतिकता के आधार पर ही यह नियोजित कर सकते हैं कि वे हाशिए के समाज के लिए कितना स्थान रिक्त रखते है।

समय रहते ही इन विषयों पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो हाशिए का समाज और भी गहरी खाई में चला जायेगा जिसे निकाल पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा।

परिशिष्ट

संजय ओझा, (उप-संपादक) दैनिक भास्कर, ब्यूरो/वर्धा

श्याम उपाध्याय, (उप-संपादक) लोकमत समाचारपत्र, ब्यूरो/वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

शोध विषय- विदर्भ में हाशिए का समाज और मीडिया

(विशेष संदर्भ: दैनिक भास्कर और लोकमत समाचारपत्र)

सक्षात्कार हेतु प्रश्नों की सूची/प्रमुख बिंदु

1 आप हाशिए के समाज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं?

2 मीडिया संगठनों में हाशिए के लोगों की कितनी भागीदारी है?

3 आप के समाचार-पत्र में हाशिए के समाज के कितने लोग कार्यरत हैं (यदि है तो किस पोस्ट पर)

4 जब समाचारों की विश्वासनीयता की बात आती है तो आप का समाचार-पत्र कितना सरोकार रखता है?

5 हाशिए के समाज के प्रति सत्ता के रवैये को आप किस तरह देखते हैं?

6 हाशिए के समाज से जुड़ी खबरों का प्रस्तुतिकरण आप किस तरह करते हैं?

7 कभी-कभी हाशिए के समाज की नकारात्मक खबरों को अधिक वरीयता दी जाती है जबकि सकारात्मक खबरों को नहीं क्यों?

8 क्या आप मानते है कि राष्ट्र विकास में हाशिए के लोगों का योगदान है?

9 हाशिए के समाज से सम्बधित घटनाओं/समाचारों को जनता के सामने लाते हैं तो उन खबरों पर प्रशासन एवं पदाधिकारियों की प्रतिक्रियाएँ किस प्रकार की होती है?

10 क्या मीडिया हाशिए के समाज के लिए विकास का उपकरण/साधन साबित हो सकता है, कैसे?

11 स्थानीय स्तर पर संबंधित समाचारों की प्राथमिक्ता पर नियंत्रण किस प्रकार होता है?

समाचारपत्र से प्राप्त चयनित विषय वस्तु (संदर्भ चित्र सूची)

<u>दैनिक भास्कर 1 जनवरी 31 जनवरी तक</u>

आदिवासी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित

एकमात्र युवती को मिली सरकारी नौकरी

जिप निर्माणकार्य सभापति के सर्कल का गांव

नहीं जुड़ते विवाह

जिले में किसानों के लिए तत्काल

कुश्ती स्पर्धा 9 से

2

आदिवासी कला मंच का दंडारी नृत्य

ब्यूरो.यवतमाल. आदिवासी कला मंच द्वारा दंडार नृत्य का आयोजन कार्ली गांव में किया गया। इस अवसर पर अपने नृत्य के प्रस्तुतिकरण के लिए दूर-दूर से कलाकार आए थे। समारोह का उद्घाटन उपजिला प्रमुख संतोष ढवले ने किया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य मंदा गाडेकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। इस समय सरपंच प्रकाश मोरे, उपसरपंच मुकिंदा भगत, उपतहसील प्रमुख सुरेश केमले, शिवसेना विभाग प्रमुख जयकुमार डहार, युवा सेना विभाग प्रमुख संतोष गदई, राजू नागरगोजे, नाना गाडेकर, गिरधर गाडेकर, विठ्ठल भोसेकर, विनोद मेश्राम, रघुनाथ कुंभेकर, नारायण कुंभेकर समेत समस्त ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

3

आदिवासी समाज के झंडे की स्थापना

ब्यूरो. वर्धा.

स्व. विठ्ठलराव मेश्राम स्मृति बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास व शिक्षा संस्था द्वारा महाबला में आदिवासी समाज के झंडे की स्थापना की गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रमोद दुमने ने की। उद्घाटक डा. ज्योति लुंगे तथा प्रमुख अतिथि के रुप में जनार्दन पंधरे, अभा आदिवासी विकास परिषद के सुनंदा पेंदामकर, ग्राप सदस्य देवराव कौरती, कोवे, राजश्री पेंदामकर, लक्ष्मण राज उपस्थित थे।

इस अवसर पर आदिवासी समाज के झंडे की स्थापना रामदास कोवे के हाथों की गयी। इस दौरान आदिवासी शोभायात्रा भी निकाली गयी।

कार्यक्रम में डा. ज्योति लुंगे ने कहा कि आदिवासी महिलाओं को एकजुट होकर समाजकार्य के लिए बचत गट के माध्यम से विकास कर ना होगा । इस दौरान सभी उपस्थित मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन किशोर मसराम ने किया। आभार गजानन कौरती ने माना। सफलतार्थ निरंजन उईके, चक्रधर मसराम, संजय कौराती, सर्जेराव देशमुख, किसना कोकडे, मडावी, सुनील कौराती, देवरा सयाम, देवीदास कौराती, गजानन कन्नाके, ओम कौराती, यश कौराती, कविता कौराती, व परिसर के समाज भाई व स्व. विठ्ठल मेश्राम स्मृति बचत गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया।

4

भादवि की धारा 324, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

खापरी में किसान ने की आत्महत्या

संवाददाता|मारेगाव. सालों से खेत में कम उपज व कर्ज बढ़ते बोझ से खापरी निवासी हरिचंद्र धुलाराम पाचभाई (42) ने अंततः तंगहाली से कीटकनाशक दवा पीकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान हरिश्चंद्र धुलाराम पाचभाई (42) ने विगत चार वर्ष पहले सगनापुर विविध कार्यकारी सोसायटी से 67 हजार रुपए का कर्ज लिया था। फसल नहीं होने से कर्ज बढ़कर 1 लाख 8 हजार रुपए पर पहुंच गया। इस साल दोबार-तिबारा बुआई के पश्चात भी फसल हाथ नहीं लगने से हरिश्चंद्र आर्थिक संकट से घिर गया था। संपूर्ण 9 एकड़ में बोई गई फसल बर्बाद होने से आखिरकार तंगहाली के चलते उसने विषैयला द्रव्य प्राशन कर आत्महत्या कर ली। वह अपने पीछे वृद्ध मां, पत्नी व दो बेटे समेत भरापूरा परिवार छोड़ गया है।

5

किसान अनुदान से वंचित

» जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता. | आर्वी.

तहसील के अहमदनगर स्थित किसान के खेत का पटवारी ने गलत तरीके से फेरफार कर किसान को 1 लाख के अनुदान से वंचित रखा। किसान ने जिलाधिकारी एन. नवीन सोना को ज्ञापन सौंपकर जांच कर अनुदान दिलाने की मांग की है।

आर्वी तहसील के अहमदनगर निवासी प्रवीणकुमार जैन का 1.87 हेक्टेयर खेत है। खेत में किसी प्रकार के संतरे के पेड़ नहीं होने के बावजूद पटवारी एस.एम. राऊत ने फेरफार कर संतरे के पेड़ दिखाए। इस कारण शासकीय फलोत्पादन कृषि विभाग द्वारा संतरे के पेड़ …

6

दैनिक भास्कर

ग्रामवासियों ने जड़ा स्कूल को ताला

बापूनगरी बनी आकर्षण का केंद्र

7

517 ग्राम पंचायतों को मिलेगी इमारत, जिला विकास योजना की बैठक

गरीबों को मिलेगी घरों की सौगात

जिला प्रतिनिधि, वर्धा.

ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए स्वतंत्र इमारत होने के साथ हर सुविधा व ई-ग्राम पंचायत का प्रावधान रखते हुए 517 ग्राम पंचायत के इमारत का प्रस्ताव तैयार करें। जिले में स्वच्छतागृह व बेघरों के लिए आवास योजना में चरणबद्ध तरीके से इंदिरा आवास योजना को प्राथमिकता देते हुए गरीबों को घरों की सौगात दिलाई जाएगी। ऐसी जानकारी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी। वे जिलाधिकारी कार्यालय सभागृह में शुक्रवार को जिले के विकास योजना की रिपोर्ट लेते समय बोल रहे थे। इस अवसर पर सांसद रामदास तडस, जिप अध्यक्ष चित्रा रणनवरे, विधायक डा. पंकज भोयर, समीर कुणावार, अमर काले, नगराध्यक्ष त्रिवेणी कुत्तरमारे, जिप उपाध्यक्ष विलास कांबले, जिप सभापति मिलिंद भेंडे, जिलाधिकारी एन. नवीन सोना, जिला पुलिस अधीक्षक अनिल पारस्कर, अतिरिक्त जिलाधिकारी संजय भागवत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद पवार, निवासी उपजिलाधिकारी सुनील गाढे सहित सभी उपविभागीय अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

उन्होंने आगे कहा कि जिले का सर्वांगीण विकास करते समय मार्ग, सिंचाई, कृषि, उद्योग आदि योजनाओं को अमल में लाएं। जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करें। प्रत्येक विभाग पांच वर्ष की विकास रिपोर्ट तैयार करें और नियोजन के दृष्टिकोण से वर्ष वार अमल में लाएं। जनता को न्याय दिलाने के लिए अधिकारी सकारात्मक कार्य करें। सार्वजनिक

शेष | पेज 14 पर

8

किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज न करें

» जायजा बैठक में विधायक बोदकुरवार ने दी हिदायत

संवाददाता | मारेगांव

सरकार की विभिन्न योजनाएं किसानों तक पहुंचाना और उन्हें उमल में लाना आज समय की जरूरत है। किसानों के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उक्ताशय की हिदायत विधायक संजीवरेड्डी बोदकुरवार ने मारेगांव में आयोजित जायजा बैठक के दौरान शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी।

विधायक बोदकुरवार की मारेगांव तहसील में यह प्रथम जायजा बैठक थी।

कृषि उपज मंडी के सभागृह में आयोजित इस बैठक में सभी विभाग के अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस समय घरकुल योजना, धड़क सिंचाई कुआं योजना, शौचालय आदि के संबंध में अधिकारी व कर्मचारी उदासीन नजर आए। इस कारण 9 लोगों के कार्य अधर में लटके होने की बात भी इस समय उजागर हुई। इस दौरान उपस्थित नागरिकों द्वारा पूछे गए सवालों का अधिकारी व कर्मचारी जवाब नहीं दे पा रहे थे। विधायक महोदय ने कुओं के प्रस्ताव तुरंत भिजवाकर भारत निर्माण योजना के शौचालय निर्माण की कार्रवाई जल्द से जल्द निपटाकर महीने भर में कार्य अमल में लाने के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत समिति स्तर की शासकीय योजनाओं की जानकारी व कार्रवाई की रिपोर्ट सप्ताहभर के भीतर देने संबंधी आदेश गुटशिक्षाधिकारी को दिए।

मारेगांव में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। पानी की समस्या हल करने के लिए मई और अप्रैल माह का इंतजार न करते हुए पहले से ही विधायक फंड में से ज्यादा से ज्यादा फंड पानी की समस्या हल करने पर खर्च किए जाने की बात उन्होंने कही। जीवन प्राधिकरण की टंकी के कार्य पर भी इस समय चर्चा की गई, साथ ही इसे जल्द पूर्ण करवाने का आश्वासन उन्होंने इस समय दिया। कृषि विभाग ने किसानों की समस्याओं को ध्यान में लेते हुए वैसा ही नियोजन करने को कहा जिससे कि, उन्हें बीज, खाद, अन्य सामग्री एवं सिंचाई सुविधा में दिक्कतें न आने पाए। निर्माण कार्य विभाग के संबंध में विधायक महोदय ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही बंद स्थिति के कार्य पुनः शुरू करने तथा कार्य की गुणवत्ता तथा तहसील पुलिस विभाग, भूमि अभिलेख, विद्युत विभाग आदि विभागों से अपने कार्य पर ध्यान दिए जाने की अपील की लेकिन किसी ने भी मारेगांव में बस स्थानक के निर्माण को लेकर सवाल नहीं उठाया। लगभग पांच घंटे चली इस बैठक में तहसील के कई नागरीक उपस्थित थे।

9

जांब में सरपंच के खिलाफ अविश्वास पारित

11 सदस्यीय ग्रामपंचायत में 9 सदस्यों ने किया प्रस्ताव पक्ष में मतदान

जांब (लोहारा) | 23 जनवरी (लोस)

मोहाड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत आनेवाले ग्राम जांब में सरपंच करुणा उके के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया.

जानकारी के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मोहाड़ी के तहसीलदार कल्याणकुमार डहाट की अध्यक्षता में 22 जनवरी को विशेष सभा बुलाई गई थी. इसमें ग्रामपंचायत के कुल 11 में से 9 उपस्थित थे, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हाथ उठाकर सहमति दर्शाई और इसी के साथ तहसीलदार कल्याणकुमार डहाट ने सरपंच करुणा उके के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की घोषणा की. बताया गया कि जांब की 11 सदस्यीय ग्रामपंचायत में सरपंच पद अनुसूचित जाति (महिला) प्रवर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण उसी प्रवर्ग की करुणा उके सरपंच पद पर आरूढ़ हुई थीं परंतु, गांव में विकासकार्यों में हो रहे विलंब, निकटवर्ती लोगों खासकर अतिक्रमणकारियों को अभय और सदस्यों को विश्वास में लेकर काम नहीं करने जैसे कारणों के चलते पिछले कुछ दिनों से सदस्यों में नाराजगी का वातावरण था. सूत्रों ने बताया, असंतुष्ट सदस्यों ने अलग गुट बनाकर विगत 16 जनवरी को तहसीलदार मोहाड़ी के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया था, जिसके बाद तहसीलदार कल्याणकुमार डहाट ने सभी सदस्यों को नोटिस तामील कर गुरुवार को विशेष सभा बुलाई थी. बताया गया कि सरपंच करुणा उके के पदमुक्त हो जाने के बाद ग्रामपंचायत का कार्यभार अब उपसरपंच सुधाकर मेश्राम पर होगा.

दुर्गम क्षेत्र में बोगस डॉक्टर कर रहे मलेरिया का इलाज

धानोरा | 23 जनवरी (लोस)

96 पीड़ित मिले

43 छात्रों को स्वर्ण

10

सैकड़ों आदिवासी सरकारी गैस सिगड़ी से वंचित

» गोदाम में धूल खा रहीं सात हजार सिगड़ियां

ब्यूरो | यवतमाल

बढ़ती जंगल कटाई पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से तथा आदिवासी परिवारों के विकास साधने के लिए राज्य सरकार की ओर से गरीबीरेखा के नीचे जीवनयापन करनेवाले आदिवासी परिवारों को निःशुल्क गैस सिगड़ियों का वितरण करने का निर्णय सात वर्ष पहले लिया गया था लेकिन इस योजना पर प्रभावी रूप से अमल नहीं हो पाने से सैकड़ों परिवारों को इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है जबकि दूसरी तरफ करोड़ों रु. खर्च कर खरीदे गए करीब 7 हजार 272 गैस के सट पिछले कई वर्षों से गोदाम में धूल खाते पड़े हैं। आदिवासी बहुल यवतमाल जिले में बढ़ती जंगल को देखते हुए इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने इन गैस सिगड़ियों के वितरण का निर्णय लिया था और गैस सिगड़ियां उपलब्ध भी करवायीं लेकिन एक ओर जहां सैकड़ों आदिवासी परिवार आज तक इसकी बाट जोह रहे हैं वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर गैस सिगड़ी के सेट कबाड़ में पड़े होने की विश्वसनीय जानकारी हाथ लगी है। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करनेवाले आदिवासी परिवारों को निःशुल्क गैस सेट देने का निर्णय आदिवासी विभाग की ओर से वर्ष 2006-07 में लिया गया था। इसके लिए एक गैस यूनिट को 1405 रुपये के हिसाब से 42 करोड़ 48 लाख 45 हजार रु. की निधि राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडल कोउपलब्ध कराया गया था। महामंडल के अधिकारियों ने लाभार्थियों की संख्या तय करने से पहले 23 हजार 911 गैस सिगड़ियों की खरीददारी कर ली थी। इस योजना में आर्थिक गड़बड़ियां भी हुईं जिनकी पोल खुलने के कारण सालभर के भीतर ही योजना का काम समेट लिया गया लेकिन इस बीच इतने बड़े पैमाने पर खरीदी गई 7 हजार 272 गैस सिगड़ियां यवतमाल स्थित गोदाम में आज तक धूल खा रही हैं। कबाड़ में तब्दील हो रही इन सिगड़ियों की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, इस कश्मकश में संबंधित विभाग है। आदिवासी बहुल क्षेत्र के नाम से पहुंचाने वाले इस जिले में आदिवासियों को ही योजना का लाभ न मिल पाने से उनके लिए कार्यान्वित की जानेवाली विभिन्न योजनाओं को लेकर संदेह जताया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं लेकिन अधिकांश योजनाओं को केवल दस्तावेजों पर ही दिखाया जा रहा है। इस ओर जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है।

नहीं हुआ संपर्क

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आदिवासी विभाग के प्रकल्प अधिकारी प्रशांत रुमाले के साथ संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन वे नहीं मिले, हालांकि दो दिन पहले ही उन्हें पंढरपुर विभाग के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है।

जलयुक्त शिवार अभियान में जनसहयो

11

आदिवासी छात्रावास में सुविधाओं का अभाव

ब्यूरो, वर्धा.

आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत चलाए जाने वाले आदिवासी छात्रावास अनेक सुविधाओं से वंचित है। शासन की ओर से निधि उपलब्ध होने पर भी विद्यार्थियों को विविध समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों की इस समस्या को कौन दूर करेगा ऐसा सवाल आदिवासी नेता अवचित सयाम ने उपस्थित किया है।

आदिवासी विभाग की ओर से आदिवासी लड़के-लड़कियों को तहसील व जिला तथा विभागीय स्तर पर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षा ले सके इसलिए जिले में 11 छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। उसमें से लड़कियों के लिए 7 व लड़कों के लिए 4 छात्रावास है। इसमें कुल 1 हजार से 1100 विद्यार्थी निवास करते हैं। शासन के मापदंड के अनुसार आदिवासी लड़के-लड़कियों को शिक्षा के प्रवाह में लाने के लिए आधुनिक सुख-सुविधाएं दी गई तथा शासन की ओर से निधि भी दी गई। फिर भी छात्रावास में अनेक सुविधाओं का अभाव दिखाई दे रहा है। शासन के नियम के तहत शासकीय छात्रावास में 40 से 50 इंच का एक कलर टीवी. तथा वैज्ञानिक एवं संशोधन चैनल के लिए डिश एंटिना व पेड चैनल के लिए 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष आवश्यक है। छात्रावास में 10 विद्यार्थियों में एक कम्प्यूटर, इंटरनेट सुविधा के साथ तथा प्रिंटर होना आवश्यक है, लेकिन उक्त सुविधा अनेक छात्रावास में नहीं दिखाई देती। अद्यावत ग्रंथालय तथा स्वतंत्र पाठ्यक्रम, आवश्यक सभी प्रकार के पुस्तक, एलसीडी कम्प्यूटर इंटरनेट के साथ फर्नीचर व ई-लायब्ररी की सुविधा होना आवश्यक है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छात्रावास में अंग्रेजी व मराठी भाषा के 5 समाचारपत्र व 10 शिक्षणपयोगी मासिक, सामान्य ज्ञान परीक्षा मार्गदर्शन व जनरल अंक अंग्रेजी व मराठी इन दोनों भाषा में आना आवश्यक है। आदिवासी विद्यार्थियों को एमपीएससी व यूपीएससी जैसी स्पर्धा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रशासन के उच्च पद पर अधिकारी बनकर देश की सेवा करें। इस समाज के लड़के-लड़कियों को प्रगति के मुख्य प्रवाह में लाकर अपने जाति के सभी सदस्यों का विकास करें इसलिए शासन के आदिवासी विभाग ने प्रतिवर्ष प्रति छात्रावास को 3 लाख रुपए स्पर्धा परीक्षा के लिए बजट में मंजूर किए लेकिन इस बाबत किसी भी छात्रावास में कोई हलचल होती नजर नहीं आ रही यह अन्याय इन आदिवासी विद्यार्थियों पर हो रहा है। निर्वाह भत्ता विभागीयस्तर पर 800 रुपए, जिला स्तर पर 600 रुपए व तहसील स्तर पर 500 रुपए हर विद्यार्थी को प्रतिवर्ष मिलता है। वो भी पूरा नहीं दिया जाता। छाता, रेनकोट के लिए हर विद्यार्थी को 500 रुपए शासन की ओर से प्रावधान है, लेकिन बारिश के मौसम में कोई भी सुविधा नहीं दिखाई देती। शैक्षणिक पिकनिक के लिए हर वर्ष प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 हजार रुपए खर्च है लेकिन छात्रावास के बच्चों की कभी पिकनिक निकाली नहीं जाती। स्नेहसम्मेलन के मनोरंजन व्यवस्था के लिए हर छात्रावास को हर वर्ष 25 हजार रुपए खर्च करना पड़ता है। लेकिन 4 छात्रावास को मिलकर एक स्नेह-सम्मेलन लेने की जानकारी है। लेकिन संबंधितों ने हर छात्रावास के स्नेह-सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर शासन से 25 हजार रुपए लेकर शासन से धोखा रहे हैं। ऐसी अन्य कितनी ही समस्याओं से ग्रस्त छात्रावास न्याय के आस में खड़ा है। शासन आदिवासी छात्रावास के माध्यम से आदिवासी विद्यार्थियों के लिए लाखों, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से विद्यार्थी कोसों दूर खड़े हैं। इस प्रकरण में राज्य के आदिवासी विभाग ने जांच कर भारतीय संविधान की धारा 46 के तहत कार्रवाई करने की मांग आदिवासी नेता अवचित सयाम ने की है। इस संदर्भ में एक आवेदन मुख्यमंत्री व आदिवासी मंत्री को ओर भेजा है।

12

अस्थायी मजदूरों ने दिया धरना

ब्यूरो | वर्धा.

जिले के कृषि विभाग अंतर्गत आनेवाले नर्सरी, टीसीडीफार्म व बिजगुनन केंद्र पर करीब 120 मजदूर अस्थायी तौर गत अनेक वर्ष से कार्यरत हैं। उनका अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 तक का वेतन बकाया है। साथ ही पुराने मजदूरों की ओर अनदेखी कर नए कामगारों को कृषि विभाग द्वारा काम पर लिया जा रहा है। जिससे गुस्साए मजदूरों ने सिटू के अध्यक्ष यशवंत झाडे के नेतृत्व में बकाया वेतन देने की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन स्थित कृषि अधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। पश्चात जिला कृषि अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान कृषि मजदूर संगठन की अध्यक्ष माला खडसे, सिटू के अध्यक्ष यशवंत झाडे, चंद्रभान नाखले, भैयाजी देशकर, महेश दुबे ने जिला कृषि अधिकारी भाऊसाहब बऱ्हाटे से चर्चा की। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी बऱ्हाटे ने पुणे के कृषि संचालक को ईमेल भेजकर मजदूरों का बकाया वेतन 31 तारीख तक देने का लिखित आश्वासन दिया। साथ ही वरिष्ठता के तौर पर इन मजदूरों को काम पर लेने का आश्वासन देने के बाद आंदोलन पीछे लिया गया। धरना आंदोलन में सैकड़ों महिला मजदूर उपस्थित थीं। ज्ञापन की प्रतिलिपि कृषि विभाग प्रधान सचिव, फलोत्पादन संचालक, विभागीय कृषि सहसंचालक, जिलाधिकारी, सांसद रामदास तडस, विधायक पंकज भोयर, जिला पुलिस अधीक्षक, थानेदार, उपविभागीय अधिकारी आदि को भेजी गई है।

13

नागपुर, रविवार, 18 जनवरी 2015

यवतमाल जिला

पानी के लिए भटक रहे वसंतनगरवासी

» गांव का कुंआ सूखा, लाखों की नल योजना बंद » चार घंटे तक पं.स.में रहीं महिलाएं

संवाददाता, मारेगांव

तहसील के आदिवासी बहुल क्षेत्र पहाड़ी में बसे वसंतनगर में दो माह से पानी के लिए महिलाओं को भटकना पड़ रहा है। इससे महिलाओं में रोष व्याप्त है। पंचायत समिति में ज्ञापन देने आए महिला-पुरुषों को चार घंटे तक रुकना पड़ा। आखिरकार प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर महिलाएं वापस लौट गईं।

तहसील से 20 किमी दूरी पर स्थित आदिवासी बहुल क्षेत्र में वसंतनगर बसा है। लगभग इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत लोग खेती करते हैं। वसंतनगर ग्राम में कुल तीन कुएं हैं, जिसमें ग्राम में स्थित कुआं सूख गया है। दो कुएं गांव से बाहर दो किमी दूरी पर हैं। चार वर्ष पूर्व इस वसंतनगर ग्राम में जलस्वराज्य योजना के तहत लाखों रुपए खर्च कर नल योजना शुरू की गई थी। नल योजना ने सभी वार्ड में पानी वितरित होने लगा, लेकिन यह

साल भर ही नहीं चल पाई। नल योजना का इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरने से यह योजना बंद पड़ गई। इस दौरान चार वर्ष की अवधि में नल योजना की पानी टंकी क्रेक हो गई तथा गांव में बिछाए गए नल के पाइप भी फूट गए। यह जानकारी वसंतनगर के ग्रामीणों ने दी।

जिसके कारण इस ग्राम में पानी की समस्या विकराल रूप लेने लगी है। ग्राम में स्थित कुआं सूखने के बाद पानी के लिए ग्रामीणों को एक किमी का फासला तय करना पड़ता है। ग्राम में इतने दिनों से पानी की समस्या होने के बाद भी पंचायत समिति द्वारा इस ग्राम में एक भी हैंडपंप नहीं लगाया गया। जिससे नागरिकों में रोष व्याप्त है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद इन आदिवासी क्षेत्र के लोग पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। दो माह से पानी नहीं मिलने के कारण उन्होंने अधिकारियों तथा विभागीय कार्यालय को जानकारी दी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार 16 जनवरी को असंख्य महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी पं.स.में दखल दी और पानी की व्यवस्था करने का निवेदन दिया। इस वक्त वसंतनगर की संगीता राठोड़, माया राठोड़, पार्वता मरापे आदि अनेक महिलाएं उपस्थित थीं।

सार समाचार

राष्ट्रीय मानवाधिकार की महिला

14

आदिवासी आश्रमशालाओं व छात्रावासों की लड़कियों का ध्यान रखना जरूरी : सयाम

ब्यूरो | वर्धा

जिले के आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत । कुल 6 शासकीय आश्रमशाला तथा सात अनुदानित आश्रमशाला व 4 शासकीय लड़कियों का छात्रावास है। इसमें करीब 700 से 800 गरीब आदिवासियों की लड़कियां माता-पिता से दूर रहकर शिक्षा ले रहीं हैं। इन सभी छात्राओं का उचित ध्यान रखना जरूरी है। उक्त विचार आदिवासी नेता अवचितराव सयाम ने प्रकल्प अधिकारी व अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपुर को भेजे ज्ञापन से व्यक्त किए हैं।

जिले में प्रमुखता से शासकीय आश्रम स्कूल नवरगांव, हीरापुर, तलेगांव, सिंदी विहिर, बोथली पांजरा, पांढुर्णा, वासी कोरा तथा अनुदानित आश्रमस्कूल वड़गांव जंगली, रोहीणी कोल्हापुर, नारा, निंबोली, वायगांव गोंड, वायगांव निपाणी, देहेगांव गोसावी, शासकीय लड़कियों का छात्रावास वर्धा में

दो, आर्वी व हिंगणघाट शहर में एक ऐसे आश्रमस्कूल व छात्रावास में कक्षा पहली से महाविद्यालयीन शिक्षा लेने वाले आयु 6 से 23 वर्ष तक की लड़कियां रहती है। आश्रम स्कूल गांव से दूर जंगल में है। शासकीय छात्रावास शहर की बस्तियों में है, लेकिन अनेक आश्रमस्कूल व छात्रावास में शौचालय, बाथरूम की सुविधा नहीं है। कड़ाके की ठंड में आवश्यक कंबल, ऊनी कपड़े, गणवेश, गाउन सही तरह से उपलब्ध नहीं होता। ठंड के दिनों में छात्राओं को ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, जिससे अनेक छात्राएं बीमारियों से ग्रस्त होती है। शासन निर्णय की तरह महिला अधीक्षक, गृहपाल, गृहप्रमुख व मुख्याध्यापक को अधिकार, जिम्मेदार व कर्तव्य की जानकारी दी गई है, लेकिन अनेक आश्रमस्कूल व छात्रावास में नियम के तहत महत्वपूर्ण पंजीयन नहीं रखा जाता। इस संबंध में आश्रमस्कूल व छात्रावास द्वारा लापरवाही बरती जाती है। हाल ही में अमरावती स्थित शासकीय छात्रावास की लड़की कुमारीमाता हुई। यह समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। जांच में स्वास्थ्य जांच न रखना तथा मासिक पीरियड के तारीख का भी पंजीयन नहीं मिला। 40 से 50 हजार वेतन लेकर भी गृहपाल या महिला अधीक्षक कुछ भी ध्यान नहीं देती। वर्धा जिले में वर्ष 2009 में स्व.गुलाबराव उईके अनुदानित आश्रमस्कूल मांडवा में कर्मचारियों ने 4 बच्चियों का यौन शोषण किया। समाज जागृति से उस आरोपी को आजन्म कारावास की सजा मिली। ऐसी घटना आश्रमस्कूलों में न हो इसके लिए छात्राओं का उचित ध्यान रखना जरूरी है। वैद्यकीय जांच नियमित करें, ऐसी मांग आदिवासी नेता अवचितराव सयाम ने की है।

अंधश्रद्धा निर्मूलन

15

किसानों के खाते में जमा होंगे 53 करोड़ 74 लाख रुपए

> प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए निधि प्राप्त

ब्यूरो | वर्धा.

खरीफ मौसम में अल्प बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के लिए सरकार ने सहायता घोषित की है। 50 पैसे से कम पैसेवारी वाले पीड़ित गांवों के किसानों को वित्तीय सहायता करने के लिए 53 करोड़ 74 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। जिसके अंतर्गत सहायता का

नागपुर विभाग के लिए 256 करोड़ 49 लाख

खरीफ मौसम में पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता करने के लिए नागपुर विभाग ने 259 करोड़ 40 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध किया है। इसमें वर्धा जिले के लिए 53 करोड़ 74 लाख, नागपुर जिले के लिए 110 करोड़ 94 लाख, चंद्रपुर जिले के लिए 85 करोड़, भंडारा जिले के लिए 8 करोड़ 9 लाख, गड़चिरोली 1 करोड़ 44 लाख तथा गोंदिया जिले के लिए 19 लाख रुपए प्राप्त हुए।

वितरण गांव वार सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक बचत खाते में जमा करने की कार्रवाई

शेष | पेज 16 पर

16

जनकी है। प्रति हेक्टेयर के लिए बीमा का लाभ उठाने के लिए 1200 रुपए की रकम भरना है। जिले के अधिक से अधिक किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी ने किया है।

धार्मिक कार्य करने तथा ग्राम स्तर पर नागरिकों में सामाजिक गठबंधन एकजुट बनाए रखने के लिए गौतम बुद्ध के बुद्ध विहार का निर्माण कार्य डॉ. बी. जी. वाघमारे के हाथों किया दिनों में नवरगांव में सामाजिक एवं धार्मिक लोगों के लिए यह एकता का प्रतीक रहेगा।

अमेरिका से आए सुधीर वाघमारे, वैशाली वाघमारे, सुषमा अवथरे, अशोक डंभारे, ज्ञानेश्वर मुन, प्रदीप रामटेके, प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुषमा माटे ने किया।

धनगर समाज को आदिवासी समाज में न शामिल किया जाए

अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की मांग

ब्यूरो | यवतमाल

धनगर समाज आदिवासी समाज में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। इसे रोकने की मांग अखिल भारतीय आदिवासी परिषद ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपे ज्ञापन में की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि धनगर समाज को आदिवासी समाज में शामिल करने की गलती न करें, साथ ही फर्जी आदिवासी प्रमाणपत्र बनाकर कई लोग इसका लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों को तलाशकर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अनुसूचित जमाति प्रमाणपत्र की जांच विनियक

2003 में किसी भी प्रकार का बदलाव न करें। आदिवासियों की जमीन साहूकार व बिल्डर्स गैरकानूनी तरीके से कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण आदिवासी जमीन कानून 1974 तथा महाराष्ट्र जमीन प्रत्यर्पित नियम 1975-76 पर शक्ति से अमल किया जाए। आदिवासियों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति-जमाति अत्याचार प्रतिबंधक नियम 1989 व 1995 जैसे कानून आदिवासियों के हित के लिए रहने के बावजूद आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले आदिवासियों की हत्या की जा रही है। राजकीय संरक्षण रहने के कारण पुलिस कानून का पालन नहीं करती। इसलिए आदिवासी कानून पर शक्ति से अमल करना चाहिए। यह ज्ञापन संगठन के विदर्भ सचिव केशव तिराणिक के नेतृत्व में सौंपा गया। इस समय आर. यू. केराम, कृष्णराव परतेकी, नारायण मडावी, श्रीरंग मडावी, रतन गेडाम, सूर्यकांत उईके, उत्तम कन्नाके, घनश्याम मडावी, उपस्थित थे।

ल का वितरण

मातोश्री विद्यालय में तकनीकी शिक्षा पर मार्गदर्शन

प्रभाग समिति में गूंजा सफाई का मुद्दा

17

की ओर जा रहे थे. इस दौरान भोयगांव से कोयला भर कर आ रहे ट्र... एम5479 ने उन्हें टक्कर मार दी. इसमें आशीष की जगह पर ही मौत ... चंद्रपुर के जिला सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया.

किसान ने की आत्महत्या

धामणगांव रेलवे | 20 जनवरी (लोस)

बेमौसम बारिश से फसलों को हो रहे नुकसान से बढ़ते कर्ज के बोझ से तंग आकर मंगलवार को 42 वर्षीय किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना तहसील के झाड़गांव में हुई.

मृतक सुभाष पारिसे है. सुभाष के पास चार एकड़ खेती थी. बुआई के लिए उसने निजी फायनांस कंपनी से 2 लाख रुपए कर्ज लिया था. कर्ज चुकाने में नाकामयाब सुभाष ने गांव के समीप रूपराव शिंगणापुरे के खेत में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. किसान के परिवार में पत्नी, दो बेटियां हैं.

अमरावती श... रही. इसके ... बजे इन कै... का डेरा होवे...

18

आदिवासी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आज

ब्यूरो. यवतमाल

सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में गोटुल बहुउद्देशीय संस्था की ओर से आदिवासी महिला सशक्तिकरण संबंधी जनजागृति कार्यक्रम का आयोजन आज 3 जनवरी को किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद की अध्यक्ष के हाथों किया जाएगा। अध्यक्षता जि.प. सदस्य मंदा गाडेकर करेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी विकास प्रकल्प अमरावती के अपर आयुक्त अशोक आत्राम, एकात्मिक विकास प्रकल्प पांढरकवड़ा के प्रकल्प अधिकारी, पारिवारिक न्यायालय की विवाह समुपदेशन अधिकारी प्रतिमा काचेवार उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम में आदिवासी बहनों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान आयोजकों की ओर से किया गया है।

19

आश्रमशाला में पेटभर भोजन भी नसीब नहीं

आदिवासी आश्रमशालाओं में भूखे विद्यार्थी

जिला प्रतिनिधि. | वर्धा.

जिले में शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रम शाला में 6 वर्ष से 18 वर्ष तक छात्र-छात्राएं रहते हैं। माता-पिता की गरीबी के कारण बच्चों को परिवार से दूर आश्रमशाला में रहना पड़ता है। आश्रमशाला में रहते हुए विद्यार्थियों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता। अधिकांश आश्रम शाला में बच्चों को आधा पेट भूखा रखा जाता है जो कि मानवता की दृष्टि से कलंक है। उक्त विचार आदिवासी नेता अवचितराव सयाम ने व्यक्त किए। वे सेलू तहसील के वडगांव जंगल में स्व. लक्ष्मणराव मानकर अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाला में अभिभावकों के साथ भेंट के दौरान बोल रहे थे। इस समय 700-800 बच्चों का भोजन बनानेवाली समिति, साफ-सफाई, बच्चों को दिया जानेवाला बेहतर नाश्ता देखकर वे अभिभूत हुए। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी समाज के अभिभावकों की अनेक शिकायतें दर्ज हैं। शासकीय व अनुदानित आश्रमशाला में रह रहे बच्चों को लेकर पालक चिंतित रहते हैं। कई शालाओं में थाली, कटोरी नहीं है। दाल के रूप में पानी परोसा जाता है, उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के नागरिकों ने माह में एक बार आश्रमशाला में भेंट देकर भोजन का दर्जा, शिक्षा का दर्जा, किताब, वैद्यकीय व्यवस्था की जांच करना चाहिए। शासन शेष | पेज 16 पर

स्प्रिंकलर के नोजल उड़ाए

सेवाग्राम. नागपुर निवासी संदीप बालकृष्ण राऊत (31) के करंजी भोगे स्थित खेत से अज्ञात चोर ने सोमवार की रात पितल के स्प्रिंकलर पाइप के 8 सेट चुरा लिए। इसमें उनका 2 हजार रुपए का नुकसान हुआ। संदीप राऊत की शिकायत पर सेवाग्राम पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया।

20

सरकारी योजनाएं: पवार

फाइल फोटो

ब्यूरो | वर्धा

प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य तत्परता से करते हुए सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना चाहिए। यह आह्वान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद पवार ने किया। कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों में समन्वय निर्माण करने तथा काम का तनाव दूर कर समस्याओं को निराकरण करने तथा किसानों को सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस वर्ष भी कृषि विभाग की ओर से क्रीड़ा व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन सांसद रामदास तड़स ने क्रीड़ा संकुल भवन में किया। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक डा. पंकज भोयर, जिला परिषद के कृषि सभापति श्यामलता अग्रवाल, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी भाऊ बनहाटे, जिला क्रीड़ा अधिकारी सुभाष रेवतकर, किसान डा. नंदकुमार तोटे उपस्थित थे। कृषि विभाग की ओर से कर्मचारी-अधिकारी के स्वप्रेरणा में स्वनिधि से प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

शासकीय छुट्टी के दिन यह महोत्सव लेकर अधिकारी व कर्मचारियों में समन्वय एवं सुसंवाद निर्माण होता है। पूरे वर्ष के काम का बोझ दूर कर किसानों के विकास के लिए प्रयास करने का आह्वान कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बनहाटे ने किया। विधायक डॉ. पंकज भोयर ने कहा कि खेल से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। किसानों की समस्याओं को सुलझाते हुए किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पहुंचाना चाहिए। इस अवसर पर किसान तोटे ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाले कृषि सहायक का सत्कार किया गया। मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरूआत की गई।

संचालन प्रवीण कडू ने किया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। डा. तोटे, बनहाटे ने क्रीड़ा मैदान का पूजन कर स्पर्धा की शुरूआत की।

21

निराधारों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ

न्याय की कर रहे प्रतीक्षा

ब्यूरो | गढ़चिरोली

सामाजिक न्याय विभाग की विशेष सहायता योजना के तहत समाज के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले जरूरतमंद, वृद्ध, निराधार, परित्यक्ता, विधवाओं और विकलांगों को सहायता मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन जिले के निराधारों और वृद्धों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों व बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि सामाजिक निराधार दुर्बल घटक तथा निराधार वयोवृद्ध अच्छा जीवन जिएं, इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग की विशेष सहायता योजना अंतर्गत संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ति वेतन योजना, इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय वृद्धापकाल निवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रिय विधवा निवृत्ति योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना व आम आदमी बीमा योजना आदि अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। किंतु जिले के लाभार्थियों को उपरोक्त योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। कई बार तो लाभ पाने के लिए सरकारी कार्यालयों में पहुंचे पीड़ित लाभार्थियों को अपमानित होना पड़ता है। कुछ बैंकों में निराधारों के खाते खोलने में अधिकारी व कर्मचारी आनाकानी करते हैं। नतीजा, आज भी अनेक लाभार्थी शासकीय लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि प्रशासकीय अधिकारी मूकदर्शक बने बैठे हैं। इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को लाभ पाने के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। फर्जी लाभार्थियों को दलाल के माध्यम से तत्काल लाभ दिए जाने से योजना के सही लाभार्थियों को वंचित रहना पड़ रहा है। प्रत्येक कार्यालय में दलालों के सक्रिय होने से निराधारों का आर्थिक शोषण हो रहा है।

22

खुले बाजार में पहुंच रहा गरीबों के हिस्से का राशन

संवाददाता | पुसद

नगर में राशन के अनाज की कालाबाजारी चरम पर है जिस कारण गरीबों के हिस्से का अनाज खुले बाजार में पहुंच रहा है और आम जनता दाने-दाने को तरस रही है। इस मामले में अन्न आपूर्ति विभाग की अनदेखी को लेकर जनता में तीव्र रोष व्याप्त है। नगर के मुखरे चौक पर स्थित शासकीय अनाज गोदाम में राशन का अनाज रखा जाता है और यहीं से तहसील के राशन दुकानदारों को अनाज का बंटवारा होता है लेकिन संबंधित विभाग में पदस्थ कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से यह राशन का अनाज खुले बाजार में पहुंच रहा है जबकि आम जनता दाने-दाने को तरसने पर विवश है। गोदाम के अधिकारियों की भूमिका भी इस मामले में संदेह के दायरे में है। चर्चा है कि, राशन का अनाज ले जानेवाले वाहन चालकों को किराये के तौर पर मोटी राशि दी जाती है जिससे यह वाहन चालक राशन का अनाज अपने वाहनों में भरकर दूरदराज, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों के गोदाम तक पहुंचाते हैं। दूसरी ओर आम जनता को अनाज से किसी न किसी बहाने वंचित रखा जाता है। विगत समय पुसद के समीप ही स्थित महागांव तहसील में करोड़ों का अनाज घोटाला उजागर होने के बाद कई अधिकारियों पर कारवाई की गाज गिर चुकी है, फिर भी आपूर्ति विभाग में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। राशन के अनाज की कालाबाजारी कर व्यापारी और अधिकारी तो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं लेकिन गरीब जनता के घरों में चूल्हे जल पाना तक मुश्किल हो चुका है। न मिट्टी तेल है, न अनाज है और न ही इस महंगाई के दौर में बाहर की दुकानों से अनाज खरीदने जितना रुपया गरीबों के पास है। ... अधिकारी कभी राशन के अनाज में हो रही गड़बड़ियों की ओर ध्यान नहीं देते जिससे यह अनाज बदस्तूर जारी है। व्यापारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से चल रही अनाज की कालाबाजारी पर पूर्ण अंकुश लगाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है।

23

एस.बी.माली, खंडविकास अधिकारी, पंस आर्वी.

गलत फेरफार से किसान का अनुदान नामंजूर

ब्यूरो | वर्धा.

आर्वी के वलीसाहब वार्ड निवासी किसान के फेरफार में गलत जानकारी दर्ज करने से किसान को फलोत्पादन योजना से मिलनेवाले अनुदान से वंचित रहने की संभावना निर्माण हुई है। इस मामले में जांच कर पटवारी पर कारवाई करने की मांग जिलाधिकारी को दिए शिकायत से की गई है। किसान प्रदीप कोमलचंद जैन ने कहना है कि उनकी अहमदनगर में खेती है। इस खेती का 11 जून 2012 को फेरफार किया गया। उनके पार्स 1.87 हेक्टेयर आर खेतजमीन होकर 28 अगस्त 2013 को खेती का सातबारा निकाला। जिसमें 11 जून 2012 को संतरा फसल सुखने का पंजीयन है। लेकिन उसके बाद निकालने गए सातबारा में 30 दिसंबर 2014 में संतरा फसल का उल्लेख ही नही किया गया है। शासकीय फलोत्पादन योजना अंतर्गत कृषि विभाग की ओर उन्होंने संतरा पेड़ो का प्रकरण प्रस्तुत किया। लेकिन सातबारा में संतारा पेड़ो का उल्लेख नही होने से उनका एक लाख रुपए का प्रकरण नामंजूर किया गया है। इस संबंध में पटवारी से पुछने पर सही जवाब नही दिया जाता। इस मामले में गहरी जांच करने की मांग पीड़ित किसान ने की है।

24

मुख्यमंत्री, पालकमंत्री को भेजा ज्ञापन

आदिवासियों को दिलाएं जमीन के पट्टे

जिला प्रतिनिधि. | वर्धा.

जंगल से सटे सेलू, समुद्रपुर, कारंजा घाडगे, आष्टी शहीद, आर्वी तहसील के अनेक भूमिहीन आदिवासी अनेक वर्षों से जंगल में जमीन अतिक्रमण कर रह रहे है। सभी अतिक्रमित आदिवासियों वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार जमीन के पट्टे मिलना जरुरी है लेकिन आज तक पट्टे दिए नहीं गए। तत्काल जमीन के पट्टे आवंटित करने हेतु आदिवासी नेता अवचितराव समया ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार को निवेदन भेजा है। भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 31 मई 2014 तक महाराष्ट्र में 3 लाख 46 हजार 230 अतिक्रमित दावे दाखिल किए गए है। जिसमें से 3 लाख 41 हजार 85 व्यक्तिक व 5 हजार 145 सामूहिक दावे है। जिसमें से 1 लाख 3 हजार 797 दावों को मंजूर कर पट्टे दिए गए जिसमें से 1 लाख 1 हजार चारसौ व्यक्ति व 2 हजार 371 सामूहिक दावे थे। वन विभाग द्वारा कुछ आदिवासियों पर अपराधिक मामले भी दर्ज कर दिए गए। महाराष्ट्र अनुसूचित जमाति व अन्य पारंपरिक वन हक अधिनियम 2006 नियम 2008 पर अमल करते हुए राज्य में 15 हजार 2 ग्रामसभा, 94 उपविभागीय स्तरिय समिति, 28 जिला स्तरिय समिति गठित की गयी। जिसका संनियंत्रण मुख्य सचिव कर रहे है। उक्त कानून पर अमल करते हुए ग्रामसभा वन हक समिति की ओर से उपविभागीय समिति में दावा प्रस्तुत किया जाता है।

जिला स्तरिय समिति की ओर से मंजूर दावे अंतिम मंजूरी समझी जाती है। सभी मंजूर दावे, प्रलंबित दावे, त्रूटी के कारण रोके गए दावों की जानकारी ऑनलाईन करने का आदेश होने पर भी ग्राम स्तर पर संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है। नियमानुसार जानकारी देकर आदिवासियों को जमीन के पट्टे दिलाने की मांग उन्होंने की है।

25

ग्रामीण अस्पताल में समस्याएं

संवाददाता| सेलू. ग्रामीण अस्पताल में व्याप्त अनेक समस्याओं के कारण मरीजों को अनेक परेशानियां हो रही हैं। रक्त जांच विभाग में कार्यरत प्रयोगस्कूल सहायक मरीजों से अच्छा बर्ताव नहीं करते। यह आरोप परिजनों ने लगाते हुए यहां की समस्याएं हल करने की मांग की है। मरीजों से अच्छी भाषा में न बोलना, देरी से आना आदि कारणों से मरीजों को परेशानी हो रही है। ग्रामीण अस्पताल के प्रयोगस्कूल विभाग में 16 जनवरी को एक मरीज ने खून की जांच की। वह मरीज 24 जनवरी को खून जांच का प्रस्ताव लेने आया था, लेकिन उस वक्त मरीज से अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। खून जांच की रसीद तक नहीं दी जाती। इस मामले की जांच करने की मांग की जा रही है।

26

26 न. का चित्र किसी कारण बस उपलब्ध नहीं हो पाया

लोकमत समाचार 1 जनवरी से 31 जनवरी तक

1

जिले में एक ही दिन चार किसानों की मौत

» चारों ने की निराशा के चलते खुदकुशी

ब्यूरो | यवतमाल

यवतमाल जिले में किसान आत्महत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। युति सरकार द्वारा हाल ही में बड़े पैमाने पर किसानों के लिए सहायता की घोषणा की गई है फिर भी निराशा से घिरे किसानों में जीवन के प्रति आस नहीं जाग रही है।

बुधवार के दिन जिले के चार किसानों की मृत्यु ने सभी को झिंझोड़कर रख दिया है। इन सभी किसानों का विषैला द्रव्य प्राशन करने के कारण स्थानीय जिला सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बुधवार सुबह सभी ने दम तोड़ दिया।

जिन चार किसानों ने कर्ज और बदहाली के चलते खुदकुशी की उनमें घाटंजी तहसील अंतर्गत ग्राम बोदड़ी निवासी बंसी सोंड्या राठोड (42) ने बुधवार तड़के ही विषैला द्रव्य प्राशन कर लिया था। उसे स्थानीय जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उस पर 30 हजार रु. का कर्ज बकाया था। तीन एकड़ खेती में वह अपनी गुजर बसर किया करता था। इसी प्रकार कलंब तहसील अंतर्गत ग्राम सोनेगांव निवासी देवराव लहरू भागवत (59) को कल रात विषैला द्रव्य प्राशन करने पर जिला सरकारी अस्पताल में लाया गया था। उस पर 36 हजार रु. का जिला मध्यवर्ती बैंक का कर्ज था। इसी तहसील अंतर्गत ग्राम देवनाला निवासी तुलसीराम कवडु राठोड (40) को 12 जनवरी की रात जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, उसके पास आठ एकड़ खेती होने के साथ उस पर बैंक ऑफ बड़ोदा का कर्ज बकाया था। इसके अलावा केलापुर तहसील अंतर्गत ग्राम मोहदा निवासी प्रकाश मनवत कुतरमारे (45) पर 30 हजार रु. का सेंट्रल बैंक का कर्ज बकाया था। उसे कल रात जिला सरकारी शेष | पेज 16 पर

विजस ने फोड़ा युति सरकार के सिर पर ठीकरा

अकालग्रस्त किसान तुअर व कपास के दाम समर्थन मूल्य से कम होने के कारण परेशान हो गए हैं। शासकीय खरीदी जल्दी शुरू नहीं हुई और व्यापारियों ने मंदी का हवाला देकर कम दाम में किसानों से उनका माल खरीद लिया। विदर्भ में इस माह में कुल 58 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। चुनाव के दौरान भाजपा व सेना ने सात बारा प्रमाणपत्र कोरा करने, बुआई खर्च के साथ 50 फीसदी मुनाफा, इस प्रकार से समर्थन मूल्य घोषित करने का आश्वासन दिया था लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। शासकीय सहायता भी पूरी नहीं दी गई है। जटिल शर्तें भी एक कठिनाई है। अकालग्रस्त किसानों को कम पैदावार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस समय कपास को छह हजार व सोयाबीन को पांच हजार रु. प्रति क्विंटल दाम दिए जाने चाहिए, इसके साथ ही अकालग्रस्त किसानों को प्रति एकड़ 25 हजार रु. अनुदान की आवश्यकता है। कर्जमाफी व नये सिरे से फसल कर्ज, अंत्योदय योजना, किसानों को रोजगार गारंटी योजना से 100 दिन का रोजगार, अकालग्रस्त किसानों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा व बेटी के ब्याह के लिए अनुदान जैसी योजनाएं शीघ्र लागू करना आवश्यक है वरना कृषक आत्महत्या थमने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

- किशोर तिवारी (संयोजक, विदर्भ जन आंदोलन समिति)

2

जिले में कुष्ठरोग के 885 नए मरीज

सावली में सबसे अधिक, 28 फरवरी तक जांच तथा जनजागृति अभियान

चंद्रपुर | 30 जनवरी (लोस)

जिले में करीब 885 नए कुष्ठरोगियों की संख्या दर्ज की गई है. गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुष्ठरोगियों की संख्या घट गई है. लेकिन अब तक पूरी तरह से कुष्ठरोग का निर्मूलन नहीं हुआ है. इसमें 19 वयस्क कुष्ठरोग की चपेट में आए हैं, तथा 97 बालक कुष्ठरोग से पीड़ित है. जिले भर में 30 जनवरी से 28 फरवरी तक कुष्ठरोग जांच अभियान तथा जनजागृति किए जाने की जानकारी कुष्ठरोग विभाग के सहायक संचालक डॉ.डी.एस. सेलोकर ने आज पत्रकार परिषद में दी.

गत वर्ष 2014 में 1 हजार 293 कुष्ठरोगियों का पंजीकरण किया गया है. कुष्ठरोग के मामले में गढ़चिरोली पहले तथा चंद्रपुर दूसरे क्रमांक पर है. इस वर्ष 885 नए कुष्ठरोग के मरीज पाए गए हैं.

इसमें 97 बच्चे भी कुष्ठरोग की चपेट में आ गए हैं. जिनपर नियमीत रूप से औषधि-उपचार शुरू है. कुष्ठरोग के 19 मरीजों पर जिले के आनंदवन तथा दो मरीजों को अमरावती जिले के कोठारी में शल्यक्रिया किए जाने की जानकारी डॉ.सेलोकर ने दी.

सावली तहसील में सबसे अधिक मरीज

डॉ.डी.एस. सेलोकर ने 'लोस' को बताया कि जिले में सबसे अधिक कुष्ठरोगियों की संख्या सावली तहसील में है. इसके बाद मूल, नागभीड़, ब्रह्मपुरी, चिमूर, सिंदेवाही, गोंडपिपरी, पोंभुर्णा आदि तहसीलों का समावेश है. राजुरा, कोरपना, ब्रह्मपुरी, वरोरा, बल्लारपुर, चंद्रपुर व जिवती तहसील में कुष्ठरोगियों का प्रमाण है. कुष्ठरोग जांच अभियान शुरू किया गया है. इसके अंतर्गत लोगों में जनजागृति की जा रही है. दवाई तथा उपचारों से कुष्ठरोग ठीक हो सकता है. कुष्ठरोग की गणना दो प्रकार में होती है. संक्रमनित तथा असंक्रमनित. असंक्रमनित रोगियों को 6 महीने तथा संक्रमनित रोगियों को 12 महीने का औषधि-उपचार करना पड़ता है.

डॉ.सेलोकर ने इस समय दी.डॉ.सेलोकर ने बताया कि पिछले वर्ष जिला परिषद, स्वास्थ्य विभाग तथा आनंदवन के संयुक्त तत्वावधान में अनुसूचित जाति व जनजाति के कुष्ठरोग पीड़ितों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आनंदवन में विविध प्रशिक्षण दिया गया. इस अंतर्गत वर्तमान में 2 पीड़ित अपना व्यवसाय कर रहे हैं तथा 9 पीड़ितों का आनंदवन में प्रशिक्षण शुरू है.राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुन कार्यक्रम अंतर्गत जिले में कुष्ठरोगियों की जांच अभियान तथा जनजागृति की जाने वाली है.

राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम अंतर्गत जिले में 757 कर्मचारियों के टीमों का चयन किया गया है. एक टीम में करीब तीन कर्मचारी होंगे, जो गांव-गांव में जाकर प्रत्येक की जांच करेंगे. इस अभियान के लिए नागरिकों ने सहयोग करने की अपील डॉ.सेलोकर ने की है. पत्रकार परिषद में डॉ.सपना तल्लारवार व डॉ.आविष्कार खंडारे उपस्थित थे.

3

सोमवार, 5 जनवरी 2015

प्रसूताओं को घंटों रखा अस्पताल से बाहर

नवजात के साथ इंतजार करती रही माताएं, विधायक के प्रतिनिधि पहुंचने पर लिया गया अंदर

राजुरा | 4 जनवरी (लोस)

ग्रामीण अस्पताल में सफाई के नाम पर आज प्रसूताओं को नवजात शिशुओं के साथ वार्ड से बाहर खुले आसमान के नीचे बिठा दिया गया. प्रसूताएं करीब 5 घंटे कक्ष से बाहर रहीं. बवाल होने के बाद विधायक के प्रतिनिधि ने डॉक्टर से बात करने पर जच्चा-बच्चा को अंदर लिया गया.

राजुरा सरकारी अस्पताल में आज सफाई करने के लिए सुबह 7 बजे वहां भर्ती मरीजो, नवजात शिशुओं के साथ उनकी माताओं को बाहर निकालकर मैदान में बैठा दिया गया. धूप होने पर इन मरीजों नें जहां छांव मिली वहीं शरण ली. कुछ धूप में ही बैठे रहे. इसकी शिकायत मिलने पर कुछ पत्रकारों ने पहुंचकर उनसे पूछताछ की. इस समय सरिता ठईके, लक्ष्मी मोहुर्ले, सावित्रीबाई गांवतुरे आदि मरीजों ने बताया कि अस्पताल के अंदर सफाई जारी है. जिससे उन्हें कक्ष से बाहर रहने को कहा गया. अस्पताल में उपस्थित प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक से पूछने पर वे पत्रकारों से ही उलझ गए. इसके पश्चात अस्पताल समिति के प्रतिनिधि उमेश मारशेट्टीवार व शिवसेना के नितिन पिपरे ने इस संदर्भ में अधीक्षक से बात की तब मरीजों को वार्ड में भेजा गया.

नवजात शिशुओं के साथ अस्पताल कक्ष से बाहर बैठी माताएं तथा उनके रिश्तेदार

मरीजों को बाहर रखना गलत: सीएस

इस मामले की शिकायत जिला शल्य चिकित्सक से करने पर उन्होंने कहा कि सफाई के लिए मरीजों को घंटों कक्ष से बाहर रखना गलत है. गलती करने के बावजूद इस संदर्भ में पूछनेवालों के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार न करना ठीक नहीं है. इस गलती के लिए उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को फटकार लगाई.

4

गलौच की. आरोपियों ने अकारण ही उन्हें जान से मारने की धमकी देकर कई थप्पड़ जड़ दिए.

किशोरी का विनयभंग

अमरावती : चांदुर बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम चिंचोली में बेलोरा निवासी आरोपी शंकर कडू ने बारह वर्षीय किशोरी को उठा लिया. आरोपी ने किशोरी का विनयभंग करने की शिकायत है. किशोरी की मां ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

5

चल रहा है. पुलिस जांच कर रही है.

महिला का विनयभंग

समुद्रपुर: डोंगरगांव निवासी महिला का विनयभंग किए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला अपने पति के साथ खेतों में काम करने गई थी. उसी दौरान आरोपी सुनील साठवणे ने पीड़िता के पति के साथ विवाद किया. बीच-बचाव करने गई पत्नी का आरोपी ने विनयभंग किया.

6

जाता है, बेकार बह जाने वाले इस पानी की कितनी मात्रा की जा सकती है और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते आदि को लेकर कार्ययोजना बनाने की अनुशंसा की गई है.

10 माह बाद भी मजदूरी से वंचित

पवनी । 31 दिसंबर (लोस)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम डोकेसरांडी में नाले का का कार्य किया गया. इसमें 125 मजदूरों के माध्यम दो सप्ताह के भीतर कार्य पूरा किया गया. इस काम पर कार्यरत मजदूरों को एक सप्ताह की मजदूरी तो दी गई, लेकिन दूसरे सप्ताह की मजदूरी रोके दस माह से अधिक समय बीत गया है. लेकिन अबतक उक्त मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी गई. इससे उन्हें आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है.

7

लोकमत समाचार | बुधवार, 7 जनवरी 2015

झरोखा

घूम-घूमकर सिल-पाटे बेच कर जीवनयापन करने वाले लोगों ने इन दिनों भंडारा जिले के पवनी में डेरा जमा रखा है. उन्होंने सड़क किनारे सिल-पाटे की दुकानें सजा ली हैं. अपनी दुकान के पास ही बैठकर रसोई बनाने के लिए बर्तन साफ करती बालिका.

न्यूज फोल्डर

4 वर्ष पर क

गोसीखुर्द की के तहत जान

लाखांदुर (भंडारा) | 6 ज

भंडारा जिले में गोसीखुर्द की बायीं नहर के सीमेंट कामों में हुए 32 करोड़ मामले में चार वर्ष बाद नहीं की गई है. सूचना के के तहत मांगी गई जानकारी में यह तथ्य सामने आया है. इस मामले में सरकार ने एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों के

8

14 यवतमाल-वर्धा जिला

करें, लेकिन शहर की स्थिति सफाई के लिए वर्ष के 2.5 करोड़

यवतमाल में जल संकट का साया

जिले के 814 गांवों का समावेश, 1 हजार 73 उपाय सुझाए, 10 करोड़ का विशेष पैकेज मंजूर

तहसीलदार को अधिकार

राजनीति से इतर तमाम खामियों को दूर करने की दिशा में जिलाधीश ने जलकिल्लत से निपटने के लिए तहसीलदार को विशेष अधिकार दिए है.

दूरगामी होंगे उपाय

जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने आगामी जलकिल्लत से निपटने के लिए अभी पूरी तैयारी कर ली. उनका प्रयास है, इससे निपटने वे दूरगामी उपाय करेंगे. उनका नैसर्गिक स्त्रोतों पर ज्यादा जोर है.

टालने के लिए नल से जलापूर्ति करने के आदेश दिए गए है. इस पर 59 लाख का खर्च किया जाएगा. 199 गांवों में नादुरुस्त नलों को दुरुस्त किया जा रहा है.

सर्वे में पाया गया, जिले के 244 गांवों के सार्वजनिक कुओं में पानी की बूंद नहीं है. ऐसे गांवों में निजी कुओं का अधिग्रहण कर जलकिल्लत को दूर करने का प्रयास किया जाएगा. इसके लिए 516 उपायों को तैयार किया गया है. इसकी पूर्ति के लिए दो करोड़ 12 लाख की निधि लगेगी. प्रशासन जिले में टैंकर की बजाय नैसर्गिक स्त्रोतों से जलापूर्ति करने पर बल दे रही ताकि आनेवाले समय में इनकी मरम्मत तथा इन पर किए गए कार्यों का नागरिकों को स्थायी रूप से लाभ मिल सकें. इस दिशा में प्रशासन ने कदम बढ़ा लिए है. हालांकि नागरिकों को पानी के लिए दर-दर भटकने की नौबत आ सकती है.

न्यूज फोल्डर

बैटरी चोरी

महिला की पर्स चोरी

खतरे में चना

उमरखेड : चार दिनों से लगातार बारिश तथा धूप नहीं निकलने से चने की फसल पर खतरा मंडराने लगा है. अब चना फसल को रोग लगने लगा है.

गुटखे की धड़ल्ले से बिक्री

टक्कर मजदूर

9

समाज कल्याण विभाग मौन

आदिवासी विकास विभाग की जांच में खुलासा, गढ़चिरोली जिले के 6 कॉलेजों में छात्रवृत्ति की राशि में ₹2 करोड़ की गड़बड़ी, प्रकल्प अधिकारी ने की पुष्टि

गढ़चिरोली। 13 जनवरी (लोस)

जिले में छात्रवृत्ति घोटाले की श्रृंखला में रोज नई जानकारी सामने आ रही है. अब जिले के 6 कॉलेजों में छात्रवृत्ति की राशि में 2 करोड़ रुपए की धांधली किए जाने की जानकारी स्वयं आदिवासी विकास विभाग के प्रकल्प कार्यालय की ओर से की गई जांच में ही सामने आई है. प्रकल्प अधिकारी और एसडीएम पी. शिवशंकर ने इसकी पुष्टि की है. इस संदर्भ में पुलिस से शिकायत भी गई है.

छात्रवृत्ति की राशि में गड़बड़ी करनेवाली संस्थाओं में गढ़चिरोली की संकल्प सिद्धी बहुउद्देश्यीय विकास संस्था, विद्याभारती कॉलेज, राहुलभाऊ बोम्मावार कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉलॉजी, सावित्रीबाई फुले इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉलॉजी, शिवनेरी कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी, सावली की साईंराम बहुउद्देश्यीय विकास संस्था, गुरुसाई कॉलेज आफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट, वडसा शिवाजी कॉलेज का समावेश है.

आदिवासी छात्रों को सरकार की ओर से दी जानेवाली छात्रवृत्ति में यह धांधली हुई है. सप्ताहभर पूर्व सामने आए इस मामले की पहली कड़ी में पी. शिवशंकर ने ही घोटालेबाजों की सीधे पुलिस में शिकायत कर इस मामले को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई. पुलिस इसकी जांच कर रही है. अब तक 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ये सभी फरार बताए गए हैं. पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है.

आदिवासी विकास विभाग ने अपनी जांच जारी रखी है. विभाग को संदेह है कि गत दिनों चामोर्शी और गढ़चिरोली शहर में सामने आए तकनीकी संस्थाओं के छात्रवृत्ति घोटाले की श्रृंखला में और भी संस्थाओं का समावेश हो सकता है. इस संबंध में पूछे जाने पर प्रकल्प अधिकारी पी. शिवशंकर ने बताया कि उन्होंने पुलिस से शिकायत कर दी है. विभाग की जांच में क्षमता से अधिक छात्र फर्जी बता कर 2 करोड़ 9 लाख 27,039 रुपयों की धांधली होने की जानकारी है.

उल्लेखनीय है कि गत सप्ताह सामने आए छात्रवृत्ति घोटाले के तार गढ़चिरोली के साथ चंद्रपुर, वर्धा और गोंदिया से भी जुड़े होने की बात सामने आ चुकी है. विभाग के ही अधिकारियों से ही सांठगांठ कर इस तरह के घपले करनेवाला कोई गिरोह होने की आशंका भी जताई जा रही है. अब गढ़चिरोली जिले के 6 कॉलेजों द्वारा छात्रवृत्ति में 2 करोड़ की धांधली किए जाने की बात स्वयं आदिवासी विभाग द्वारा ही उजागर किए जाने से शिक्षा क्षेत्र में हलचल मच गई है. और भी संस्थाओं के इसमें लिप्त होने की आशंका है. आदिवासी विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग से यह धोखाधड़ी इन संस्थाओं द्वारा की गई है. आदिवासी विकास विभाग ने इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है. परंतु समाज कल्याण विभाग की ओर से अब तक इस दिशा में कोई आधिकारिक बयान या टिप्पणी नहीं आयी है. सरकार के साथ इतनी बड़ी धांधली और छात्रों के साथ खिलवाड़ की इतनी गंभीर घटना में अब आरोपियों के खिलाफ रवैया कितना गंभीर और सख्त होगा, इस ओर सभी का ध्यान लगा है.

छात्रवृत्ति घोटाला

अमरावती में फायरिंग मामले के और 4 आरोपी गिरफ्तार

शेख जफर आज करेंगे सरेंडर

अमरावती के चांदनी चौक के फायरिंग

मेडिकल स्टोर

10

इंतजार ₹6.30 करोड़ के प्रस्तावों को अब तक नहीं मिली है सरकारी मंजूरी

आदिवासी छात्रावास अधर में

जिले में हैं 97,718 आदिवासी

11

झोपड़ी जलकर खाक परिवार सड़क पर

बच गया परिवार

12

मार्गदर्शन करते अंबरीश आत्राम.

आदिवासियों के विकास के लिए करेंगे प्रयास

राजुरा। 12 जनवरी (लोस)

13

चंद्रपुर जिले के 350 किसानों ने मांगी आत्महत्या करने की अनुमति

पालकमंत्री से की चर्चा

शंकरपुर। 24 जनवरी (लोस)

किसान ने दी जान

14

इधर बैंक के खाते नहीं, उधर कर्ज बकाया

कैसे उबरेगा किसान

4782 साहूकार के कर्जदार

29% के नहीं खुले खाते

यवतमाल। 18 जनवरी (लोस)

15

त्रासदी किसान आत्महत्या रोकने 'आप' ने मुख्यमंत्री को भेजा सुझाव

10 साल में 413 किसानों ने दी जान

16

यवतमाल-वर्धा

घाटंजी में कपास खरीद बंद

किसानों ने किया रास्ता रोको

घाटंजी। 3 जनवरी (लोस)

आरोपी को छह माह की सजा

परिचर पद की परीक्षा आज

17

किसानों के बैंक खाते में नहीं पहुंची मदद राशि

» देवली, आर्वी, सेलू तहसील के किसानों के खातों में एक भी पैसा नहीं

18

विदर्भ के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार

व्याख्यान में श्रीहरि अणे का प्रतिपादन

गोंदिया। 16 जनवरी (लोस)

जानकारी

आत्मसमर्पित नक्सली कमांडर गोपी उर्फ

19

ट्रांसपोर्ट नगर की 100 झोपड़ियां हटाई

महापालिका के तोड़ू दल ने की कार्रवाई, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त

अमरावती। 14 जनवरी (लोस)

ट्रांसपोर्ट नगर में अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद खुले में सामान समेटते लोग.

बढ़ा तनाव

आरक्षित है जमीन

20

भंडारा जिले के 154 गांवों में सूखा

पैसेवारी 50 से कम, 21 गांवों में इस बार नहीं हुई धान की फसल

खरीफ में नहीं ली जाती धान की फसल!

राहत में क्या-क्या

ल पुल से टकराई, दो मृत

दो किसानों ने की आत्महत्या

21

वणी से मारेगांव जा रही बस का संतुलन बिगड़ा के किनारे गड्ढे में फंस गई. इस हादसे में कोई ह सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं.

माल-वर्धा

10 दिनों में 16 ने दी जान

नहीं जागी सरकार, मुसीबत के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे, संकट में किसान

25 को देशभक्ति पर समूह गीत गायन स्पर्धा

प्रेरणास्थल आयोजन समिति, हनुमान शाला क्रीड़ा मंडल का आयोजन

बैंक से निकाली ₹25 हजार की राशि

22

ठिठुरते लोगों को बांटे गए कंबल

वित मंत्री की पत्नी ने बेसहारा लोगों की सुध ली

चंद्रपुर। 11 जनवरी (लोस)

बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर कंबल बांटतीं सपना मुनगंटीवार, कांता ढोके व अन्य.

23

सुनंदा माडावी प्रमुखता से मौजूद थे.

स्वास्थ्य जांच की गई

वर्धा: आर्वी नाका परिसर स्थित झोपड़पट्टी में जिला अस्पताल द्वारा लोगों की स्वास्थ जांच की गई. शिविर को सफल बनाने में न्यु आर्ट्स, कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालय के छात्रों नणे सहयोग दिया. बस्ती में लोगों को साफ-सफाई के बारे में जानकारी दी गई.

24

ग्रुप तथा अंबानगरीवासियों की ओर से आयोजित रामकथा में आए संतश्री चिन्मयानंद बापू मरीजों को ब्लैंकेट बांटते हुए.

अपना विदर्भ

नागपुर, शनिवार, 10 जनवरी 2015

रहने को घर नहीं

इन लोगों के लिए क्या जीवन अभावों का नाम ही बन गया है. जबर्दस्त ठंड में जहां बंद कमरे में भी आदमी ठिठुर जाता है, वहीं अमरावती के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्थानक परिसर तथा राजकमल चौक के उड़ान पुल के नीचे ठंड से जूझते हुए भी मजबूरी में नींद लेते गरीब नागरिक. एक ने तो अपने रिक्शे को ही सोने का बिस्तर और पलंग बना लिया है, जबकि जोशी मार्केट में चौकीदारी करने वाले भी ठंड से परेशान होकर कंबल ओढ़ कर राहत महसूस कर रहे है.

ट्रक-बाइक की

25

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आने की बजाए बढ़ोत्तरी होती जा रही है. यह चिंता का विषय है. 11 जनवरी को सड़क सुरक्षा अभियान प्रारंभ किए जाने के बाद लिए कम जिम्मेदार नहीं है. वे नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलानेवालों पर कार्रवाई की बजाए अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में अधिक दिखाई पड़ते हैं. जिले में

12 दिनों से लापता है महिला

प्रतापगढ़ जंगल परिसर में गई थी लकड़ियां चुनने

अर्जुनी मोरगांव। 20 जनवरी (लोस)

तहसील के चिचोला (जूनी) गांव की निवासी महिला मंगला टीकाराम शेंडे (34) विगत 7 जनवरी को प्रतापगढ़ जंगल परिसर में ईंधन के लिए लकड़ियां चुनने गई थी. लेकिन 13 दिन बीत जाने के बावजूद उसके वापस न लौटने से परिसर में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगला ईंधन के लिए लकड़ियां चुनने की बात कहकर 7 जनवरी को सुबह घर से निकली. लेकिन शाम तक उसके न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. इसके बावजूद उसका कोई पता न लगने पर टीकाराम ने केशोरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है. प्रतापगढ़ जंगल परिसर में विभिन्न प्रकार के वन्यप्राणियों के विचरण से उस पर जानवरों द्वारा हमला किए जाने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है. पुलिस विभाग ने वनविभाग के कर्मचारियों एवं जानवरों को चरानेवाले चरवाहों को भी घटना की जानकारी देकर जांच में सहकार्य करने को कहा. लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल सका है.

सट्टापट्टी लेते बंदी

गोंदिया: शहर पुलिस ने वाजपेई वार्ड निवासी संजय सार्वे (42) को सट्टापट्टी लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से 320 नगद एवं सट्टापट्टी जब्त की गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

संगीत संध्या 23 को

26

पहल | जिला परिषद के जलापूर्ति विभाग के प्रयासों से डोमनी गांव को मिलेगी राहत

30 साल बाद गांव होगा टैंकरमुक्त

अमरावती। 30 जनवरी (लोस)

पिछले 30 से 35 साल से चिखलदरा तालुका के डोमनी फटा गांव को टैंकर से जलापूर्ति की जाती थी. लेकिन अब यहां के नागरिकों का जल संघर्ष जल्द समाप्त होने वाला है.

जिला परिषद के जलापूर्ति विभाग के जरिए हर वर्ष ग्रीष्मकाल में डोमनी गांव को टैंकर से जलापूर्ति करनी पड़ती थी. डोमनी फटा गांव बिहाली से करीबन 80 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बसा है. यहां के नागरिकों को पहाड़ के नीचे से पानी लाना पड़ता था. ग्रीष्मकाल के दिनों में जिस स्थल से पानी की प्यास बुझाई जाती थी, वहां से पानी उपलब्ध नहीं होता था. तब इस गांव को जिला परिषद के जलापूर्ति विभाग द्वारा टैंकर से जलापूर्ति की जाती थी. 183 की आबादी वाले इस गांव को कायम स्वरूप पानी की व्यवस्था करने के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी के मार्गदर्शन में कार्यकारी अभियंता श्वेता बैनर्जी ने अधिकारियों की सहायता से जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव शासन के सामने प्रस्तुत किया था. करीबन 18 लाख रुपए के इस प्रस्ताव को राज्य के जलापूर्ति विभाग ने मंजूरी दी. पश्चात डोमनी फटा गांव में जलापूर्ति विभाग ने पहाड़ी के नीचे बोअरवेल कर पाइप लाइन बिछा कर गांव तक पानी पहुंचाया. गांव में करीबन 10 हजार लीटर की पानी की टंकी, जल वितरण व्यवस्था जैसी सुविधा उपलब्ध कर दी गई है.

यह योजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. कुछ समय में पूरे होते ही इस गांव को पेयजल कायम स्वरूप उपलब्ध होने वाला है. विशेष यानी गणतंत्र दिवस पर इस योजना का प्रायोगिक तत्व पर ट्रायल भी लिया गया. आगामी मार्च माह के पूर्व इस गांव को टैंकर मुक्त किया जाने वाला है. जिला परिषद के जलापूर्ति विभाग ने इसके पूर्व मेलघाट के माखला, मेमना, लवादा, केकदाखेड, मालूर वन आदि गांवों को टैंकरमुक्त किया है.

27

बगीचा निर्माण के लिए इस परिसर की सफाई की जा रही थी, उस समय यह

कामगारों को तीन माह से नहीं मिला वेतन

बंद पड़ा खड़संगी का पॉवर प्लांट

खड़संगी। 29 जनवरी (लोस)

चिमूर एमआईडीसी परिसर में कोई बड़ा उद्योग न होने से यहां पर वर्ष 2009 से दस मेगावॉट का शरद अंबिका पॉवर प्लांट शुरू किया गया. इसमें परिसर के 200 से अधिक बेरोजगारों का काम मिला लेकिन पॉवर प्लांट तीन साल चलने के बाद बंद हो गया. इसे पूर्ववत शुरू नहीं किए जाने से यहां के कामगारों में रोष व्याप्त है.

बंद पड़ा खड़संगी स्थित पॉवर प्लांट.

कामगारों का वेतन तीन महीने से प्रलंबित है. लेकिन पॉवर प्लांट प्रबंधन का इस ओर ध्यान नहीं है. पॉवर प्लॉट का मालिक आंध्र प्रदेश से है. आंध्र प्रदेश में उसका दूसरा पॉवर प्लांट है. इसलिए वह इस प्लांट की ओर ध्यान नहीं देने की शिकायत है. वेतन मांगने पर पॉवर प्लांट मालिक उन्हें प्लांट शुरू होने के बाद वेतन देने की बात कर रहा है. वेतन तथा काम न मिलने से कामगारों पर भूखे मरने की नौबत आ गई है.

शाला इमारत में

10 घंटे बं

28

करीब 15 से 18 किमी है. इतनी दूर से सिलेंडर लेकर मोटरसाइकिल या अन्य वाहन से यात्रा करना खतरे से खाली नहीं जिससे एजेंसी संचालकों की मनमानी और बढ़ गई है. भद्रावती के भद्रनाग गैस एजेंसी में नंबर लगाने के एक-एक महीने तक

आदिवासियों को कल्याण राज्यमंत्री से है काफी उम्मीद

आज राजुरा में आगमन

राजुरा। 11 जनवरी (लोस)

स्वामी विवेकानंद जयंती महोत्सव के अवसर पर भाजपा के सदस्य पंजीयन अभियान का शुभारंभ राजुरा विधानसभा क्षेत्र में आशादेवी मंगल कार्यालय में आज किया जाएगा, जिसमें राज्य के आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे. उनसे क्षेत्र के आदिवासियों को काफी उम्मीद है.

आदिवासी बहुल क्षेत्र माने जानेवाले राजुरा क्षेत्र में नवनिर्वाचित आदिवासी राज्यमंत्री का यह पहला दौरा है. उनसे न्याय मिलने की उम्मीद आदिवासी समाज बंधुओं द्वारा जताई जा रही है.

स्थानीय कोलामगुड़ा, भाई पठार के सैकड़ों आदिवासियों के पास प्रमाणपत्रों का अभाव होने के चलते उन्हे जाति प्रमाणपत्र से वंचित रहना पड़ा है. सैकड़ों आदिवासियों की जमीन का पट्टा अब तक नहीं मिला है. कोलामगुडा में झोपड़ियों में रहने को आदिवासी मजूबर हैं. वहां न रास्ता है, न पानी हैं. दयनीय स्थिति में वे अपना जीवन गुजार रहे हैं. सरकार व प्रशासन उनकी दखल नहीं ले रहे. अब आदिवासी मंत्री के आने से वे उम्मीद भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे हैं कि वे उनके लिए कुछ करेंगे.

चटाई बनाती आदिवासी कोलाम महिला

परेड मैदान पर सड़क सुरक्षा

29

समस्या | ठंड में ठिठुरते और बरसात में भीगने को मजबूर हैं निराधार नागरिक

बेघरों के लिए नही है 'रैन बसेरा'

चंद्रपुर। 14 जनवरी (लोस)

बेघर-बार लोगों को ठंड तथा बरसात में आश्रय के लिए रैन बसेरा बनाने की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है, लेकिन चंद्रपुर महानगरपालिका क्षेत्र में अब तक एक भी रैन बसेरा नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से बेघर-बार लोगों को मंदिर और सार्वजनिक स्थलों की आड़ में ही तूफानी रातें व कड़कड़ाती ठंड गुजारनी पड़ती है.

चंद्रपुर जिले में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके पास रहने के लिए आशियाना नहीं है. जो सक्षम हैं वे किराए का मकान ले लेते हैं, किंतु जो भीख मांगकर अपनी आजीविका चलाते हैं, लावारिस हैं वे खुले आसमान के नीचे ही जीवन गुजारते हैं. जब तेज बारिश होती है तो किसी मंदिर या अन्य सार्वजनिक स्थल में जाकर आश्रय लेते हैं. लेकिन वहां भी उन्हें ज्यादा समय रहने के लिए नही दिया जाता.

ठंड में वे खुले आसमान के नीचे ही ठिठुरते रहते हैं. ऐसे में कड़ाके की ठंड से कई लोगों की मौत हो जाती है. ऐसे लोगों को ठंड व बरसात से बचाने की जिम्मेदारी सरकार तथा स्थानीय निकायों की है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे चंद्रपुर सहित राज्य के कई महानगरों की यही हालत है, जहां रैन बसेरों का सर्वथा अभाव है. वहां के लोग ठंड में ठिठुरकर मरने को मजबूर हैं. यदि चंद्रपुर महानगर में एक-दो स्थानों पर रैन-बसेरा का निर्माण हो जाए तो सैकड़ों बेघर-बार, लाचार लोगों को चैन से रात गुजारने का स्थान मिल जाएगा.

रैन बसेरा में आराम करते बेघर नागरिक.

अभी कुछ समय लगेगा : शंभरकर

इस बारे में मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर ने बताया कि चंद्रपुर महानगरपालिका क्षेत्र में भी रैन-बसेरा बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन उसके लिए अभी कुछ समय लगेगा.

स्कूलों में आश्रय देने का था प्रस्ताव : तिवारी

चंद्रपुर मनपा की स्थायी समिति के सभापति रितेश उर्फ रामू तिवारी ने 'लोस' को बताया कि पिछले वर्ष ठंडी में बेसहारा लोगों को रात गुजारने के लिए स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था. इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. इस बात को गंभीरता से लेना अब जरूरी हो गया है.

30

साकोली तहसील के वड़द गांव में तेईस किसानों के समूह द्वारा लगाई गई आलू की फसल का

आलू की फसल लगाई.

गत 6 नवंबर को उन्होंने आलू की बुआई की और मात्र दो महीनों में ही फसल लहलहा उठी. उन्होंने कुफ्री चिप्सोना-3 और कुफ्री बहार प्रजाति के बीज बोए हैं. आलू की उम्दा किस्म के चिप्स बनाने के लिए यह प्रजातियां मशहूर हैं और बाजार में उनकी मांग भी अधिक है. उम्मीद जताई गई है कि आलू की उपज 15 फरवरी तक निकल आएगी. जिला कृषि विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में वड़द का दौरा कर वहां लगाई गई आलू की फसल का

शहरों में भी बढ़ रहा कुपोषण

एकात्मिक बालविकास सेवा योजना के तहत आंगनवाड़ी में हुए सर्वेक्षण में उजागर

यवतमाल। 11 जनवरी (लोस)

राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में जहां कुपोषण की दाहकता कम नहीं हो रही है, वहीं शहरी क्षेत्रों में भी कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है. राज्य के विविध शहरों में किए गए सर्वेक्षण में यह बात उजागर हुई है. शहरी क्षेत्रों में 17 फीसदी बच्चे मध्यम या कम वजन वाले हैं, जो कुपोषण की श्रेणी में आते है.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की विविध आंगनवाड़ियों में किए गए सर्वेक्षण में यह बात उजागर हुई है. विदर्भ के आदिवासी बहुल गढ़चिरोली, चंद्रपुर, भंडारा, यवतमाल, अमरावती जिलों में आदिवासी घरों में जन्म लेने वाले बच्चे जहां कुपोषित है, वहीं नागरी क्षेत्र में भी कुपोषित बच्चों की संख्या कम नहीं है. शहरी क्षेत्रों में 6 वर्ष तक के 15 लाख 54 हजार बच्चों का सर्वेक्षण किया गया.

इसमें से 10 लाख 62 हजार बच्चों का वजन किया गया. इनमें 8 लाख 81 हजार बच्चे सामान्य वजन के तथा 1 लाख 80 हजार बच्चे मध्यम एवं तीव्र कम वजन वाले पाए गए. कुपोषित बच्चों की संख्या 17 फीसदी बताई जाती है, जो कम नहीं आंकी जा सकती. शहरी क्षेत्रों में झोपड़पट्टी में रहनेवाले लोगों ने अज्ञानता, गरीबी, स्वास्थ्य मार्गदर्शन की कमी, निरक्षरता आदि के चलते बच्चों में कुपोषण का प्रमाण बढ़ रहा है.

यवतमाल जिले में भी 8,790 बच्चे कुपोषित होने की बात प्रकाश में आई है. स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में उचित कदम नहीं उठा रहा है. मालेगांव एवं नागपुर जैसे शहरों में भी कुपोषित बच्चों की संख्या कम नहीं है. इस संदर्भ में सरकार से उचित उपाय करने की मांग की जा रही है.

कुपोषण

विदर्भ के अकाल पर

ऑटो चालक गंभीर

31

सहूलियत | 25 नवंबर की रिपोर्ट के आधार पर घोषणा, 50 पैसे से कम पैसेवारी का मामला

जिले के 1981 गांवों में किल्लत

अमरावती। 22 जनवरी (लोस)

वर्ष 2014-15 के खरीफ फसल मौसम में आई बेमौसम बारिश तथा शुरुआती दौर में रही अकाल की स्थिति के कारण उत्पादन का प्रतिशत घटा है. जिला प्रशासन द्वारा गांवों में किए सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जिले के 1981 गांवों को पैसेवारी के मामले में किल्लतग्रस्त घोषित किया है.

जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के आदेश के बाद 1986 गांवों का प्रस्ताव भेजा था, किंतु इनमें से केवल 1981 गांवों को मंजूरी दी गई है, जबकि पांच गांवों को सूची से हटाया गया है.

जिले की पैसेवारी

तहसील	गांव	पैसेवारी	तहसील	गांव	पैसेवारी
अमरावती	143	46	वरुड	140	45
भातकुली	137	44	अचलपुर	184	44
नांदगांव खंडेश्वर	161	42	चांदुरबाजार	171	43
चांदुर रेलवे	90	46	दर्यापुर	150	45
धामणगांव रेलवे	112	42	अंजनगांव सुर्जी	127	39
तिवसा	95	40	धारणी	152	48
मोर्शी	156	37	चिखलदरा	163	48

काम में दिलासा, पीने के पानी की गांव में टैंकर से जलापूर्ति, किसानों को कृषि पंप बिजली कनेक्शन तोड़ने में राहत दी जाएगी. ऐसी जानकारी जिलाधीश किरण कुमार गित्ते ने दी है. साथ ही इस संबंध के आदेश तहसीलों को दिए गए है.

32

ग्रामीण स्वास्थ केंद्रों की हालत खस्ता

काली (दौ)। 28 जनवरी (लोस)

ग्रामीण परिसर के गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को बेहतर स्वास्थ सुविधा देने के लिए सरकार करोड़ो रुपए पानी की तरह बहा रही है. लेकिन, समाज के आखिरी स्तर तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है. स्वास्थ सेवा देने के लिए शुरू किए गए ग्रामीण स्वास्थ केंद्रो की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है. यह स्थिति मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है.

इन केंद्रो का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है. यहां कई बार चिकित्सक नहीं रहते हैं. तो कभी दवाइयां खत्म हो जाती है. ऐसे में यदि गंभीर हालत में मरीज का इलाज नहीं हुआ तो मरीज की जान भी चली जा सकती है. लेकीन, आधिकारियों को इस बात से कोइ सरोकार नही है.

मरीजों को यह भी नहीं बताया जाता है कि डॉक्टर साहब आएंगे भी या नहीं. कर्मचारियों की वजह से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. लोगों से जिला चिकित्सक से इस ओर ध्यान देने की मांग की जा रही है.

33

पिछले 10 वर्षों में 102 किसानों ने दे दी जान

वर्ष 2013-14 में सर्वाधिक 27 किसानों ने लगाया मौत को गले

पुसद। 2 जनवरी (लोस)

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक एवं सुधाकरराव नाईक की कार्यशैली से पावन हुए पुसद तहसील में विगत 10 वर्षों में फसल की कमी, कर्ज का बोज तथा अकाल से त्रस्त एक महिला किसान समेत 102 किसानों ने आत्महत्या कर ली. जिसमें वर्ष 2013-14 में सर्वाधिक 27 किसानों ने मौत को गले लगाया. सरकार के पास केवल 44 किसानों की मौत के आकड़े पहुंच पाए हैं. जिन्हें सरकारी सहायता के लिए पात्र घोषित किया गया. वर्ष 2003-04 में पांच किसानों ने आत्महत्या कर ली. इनमें से केवल दो किसानों को सरकारी योजना का लाभ मिला. वर्ष 2005 में दो किसानों ने आत्महत्या की. वर्ष 2006 में 22 किसानों ने विविध कारणो से मौत को गले लगा लिया. इनमें से केवल सात को सरकारी योजना के लिए पात्र घोषित किया गया. वर्ष 2007 में आत्महत्या किए 11 में से चार और वर्ष 2008 में छह किसानों में से मात्र दो किसानों को सरकारी सहायता मिली. वर्ष 2009 में चार किसानों ने आत्महत्या को गले लगाया. इनमें से एकमात्र किसान को सरकारी लाभ मिला. वर्ष 2010 में छह किसानों ने आत्महत्या की सरकारी सहायता दो किसान परिवार को मिली. वर्ष 2011 में छह किसानों ने आत्महत्या की. चार परिवार को सहायता दी. वर्ष 2012 में 13 किसानों ने आत्महत्या की. केवल छह परिवार को सरकारी योजना के लिए पात्र समझा गया. 2013 में 15 किसानों ने और 2014 में छह किसानों ने मौत को गले लगा लिया. इन परिवारों को अब तक सहायता नहीं दी गई है.

34

आयोजन | गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में पालकमंत्री आत्राम ने दिए निर्देश

अंतिम छोर तक विकास योजना पहुंचाएं

गढ़चिरोली। 26 जनवरी (लोस)

जिले का विकास करने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रशासन को प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा. अंतिम छोर पर बसे आम आदमी तक योजनाओं को पहुंचाएं और नागरिकों के साथ समन्वय रखते हुए प्रशासन से कार्यप्रणाली में गति लाने का अनुरोध राज्य के आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री अंबरीशराव आत्राम ने किया.

मुख्य ध्वजारोहण समारोह के दौरान मार्गदर्शन करते हुए पालकमंत्री अंबरीशराव आत्राम.

35

घर में आग लगने से गरीब परिवार पर बरपा कहर

गृहस्थी की सामग्री खाक

संवाददाता | केलझर.

वार्ड नं. 5 में अज्ञात लोगों ने एक घर को आग लगा दी। आग में 2 लाख की सामग्री जलकर खाक हो गई। घटना के समय घर के सभी सदस्य खेत में मजदूरी के लिए गए हुए थे। घर में मौजूद बच्चों ने शोरशराबा मचाते हुए आस-पास के नागरिकों को मदद के लिए बुलाया लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। घटना शेष | पेज 16 पर

लोगों ने दिया आश्रय

कसदेकर परिवार के सिर से छत छीन जाने के कारण रात में कड़ाके की ठंड को देखते हुए आस-पास के लोगों ने अपने घर में उन्हें आश्रय देते हुए भोजन की व्यवस्था की। सुबह गांव के जनप्रतिनिधियों ने कपड़े व अनाज देकर मदद की और 19 जनवरी की शाम तक शासन की ओर से भी मदद मिलने के कारण गरीब परिवार को थोड़ी राहत मिली।

दो जून रोटी के लाले

बालाजी लालाजी कसदेकर के परिवार में 9 व्यक्ति है। आर्थिक स्थिति तंग होने के कारण सभी दूसरों के खेत में मजदूरी के लिए जाते हैं। अनाज, कपड़े व नगद रकम जलने के कारण गरीब परिवार पर खाने के लाले पड़ गए हैं।

36

लोकमत समाचार
अपना विदर्भ
नागपुर, गुरुवार, 1 जनवरी 2015

200 गरीब वृद्धों को कंबल का वितरण

वृद्ध को ब्लैंकेट देते अन्न सुंदरगिरि तथा शंकर तेलंग.

37

ध्यानाकर्षण | प्रभाग क्रमांक 4 में झोपड़पट्टी व पीने के पानी की समस्या

क्षेत्र के 100 परिवारों पर गिरेगी गाज

मकान खाली करने की नोटिस

38

कार्यक्रम का संचालन युनियन के सचिव सोमराज उरकुड़े एवं आभार प्रदर्शन दड़वी किया. कार्यक्रम में सभी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

ग्रामीण अस्पताल में असुविधा

मोहाड़ी : तहसील के ग्रामीण अस्पताल में असुविधाओं से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं यहां के व्यवस्था में नियोजन का अभाव है. इस कारण मरीजों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इस कारण मरीजों को दिक्कतें उठानी पड़ रही है. नागरिकों ने अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है.

ऑनलाइन आवेदन करें

गढ़चिरोली : आदिवासी विकास विभाग की

39

रोजनामचा

ग्रामीण अस्पताल में विवाद

यवतमाल | समीपस्थ नेर के ग्रामीण अस्पताल में किसी काम से आए व्यक्ति के साथ वैद्यकीय अधिकारी का विवाद हो गया जो हाथापायी में तब्दील हो गया। इस मामले में वैद्यकीय अधिकारी ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ दर्ज शिकायत में उनकी जेब से चार हजार रु. छीन लिए जाने तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। घटना गुरुवार की शाम 5.15 बजे की बतायी जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेर निवासी विजय उमरतकर किसी काम से ग्रामीण अस्पताल में आया हुआ था। इस दौरान किसी बात को लेकर विजय अस्पताल में कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी संजय आर. जाधव (40) से उलझ गया। विवाद अच्छा-खासा बढ़ गया और विजय और वैद्यकीय अधिकारी जाधव के बीच हाथापायी हो गई। इसके बाद वैद्यकीय अधिकारी जाधव ने नेर थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवायी जिसमें उन्होंने विजय पर उनकी जेब से 4 हजार रुपए छीनकर उन्हें जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में वैद्यकीय अधिकारी जाधव की शिकायत पर नेर पुलिस ने आरोपी विजय उमरतकर के खिलाफ भादंवि की धारा 392, 353, 294, 506 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

खुदकुशी मामले में पत्नी समेत तीन नामजद

जलशुद्धिकरण केंद्र का निरीक्षण

नक्सल क्षेत्रों में उजागर हो रहा छात्रवृत्ति घोटाला, वर्धा की संस्थाओं का समावेश

गैरआदिवासियों के नाम पर डकारी राशि

40

प्रकाशित खबरों की सूची

क्र.	चित्र सं.	प्र.सं	दिनांक	संदर्भ विवरण
1	1	13	01-01-2015	दैनिक भास्कर
2	2	17	02-01-2015	दैनिक भास्कर
3	3	13	03-01-2015	दैनिक भास्कर
4	4	15	04-01-2015	दैनिक भास्कर
5	5+1	14.18	05-01-2015	दैनिक भास्कर
6	6	17	06-01-2015	दैनिक भास्कर
7	7	13	08-01-2015	दैनिक भास्कर
8	8	17	10-01-2015	दैनिक भास्कर
9	9+1	13.16	11-01-2015	दैनिक भास्कर
10	10+1	16.17	12-01-2015	दैनिक भास्कर
11	11	16	14-01-2015	दैनिक भास्कर
12	12+1	13.16	15-01-2015	दैनिक भास्कर
13	13	17	18-01-2015	दैनिक भास्कर
14	14	16	19-01-2015	दैनिक भास्कर
15	15	13	20-01-2015	दैनिक भास्कर
16	16+1	13.16	21-01-2015	दैनिक भास्कर
17	17	17	22-01-2015	दैनिक भास्कर
18	18	13	24-01-2015	दैनिक भास्कर
19	19	16	26-01-2015	दैनिक भास्कर
20	20	17	27-01-2015	दैनिक भास्कर
21	21	13	28-01-2015	दैनिक भास्कर
22	22	15	29-01-2015	दैनिक भास्कर
23	23	18	31-01-2015	दैनिक भास्कर
24	24			
25	25			
26	26		**Total -28**	
27	27			
	Total-28			

क्र.	चित्र सं.	प्र.सं	दिनांक	संदर्भ विवरण
1	1+1+1	14+1.16	01-01-2015	लोकमत समाचार
2	2	12	02-01-2015	लोकमत समाचार
3	3+1	12.13	03-01-2015	लोकमत समाचार
4	4+1	11.12	04-01-2015	लोकमत समाचार
5	5+1	11.12	05-01-2015	लोकमत समाचार
6	6	12	06-01-2015	लोकमत समाचार
7	7	12	07-01-2015	लोकमत समाचार
8	8+1	12.14	08-01-2015	लोकमत समाचार
9	9	11	09-01-2015	लोकमत समाचार
10	10	13	10-01-2015	लोकमत समाचार
11	11	11	11-01-2015	लोकमत समाचार
12	12+1+1	11.16+1	12-01-2015	लोकमत समाचार
13	13	16	13-01-2015	लोकमत समाचार
14	14	11	14-01-2015	लोकमत समाचार
15	15+1+1	11,12,13	15-01-2015	लोकमत समाचार
16	16	11	16-01-2015	लोकमत समाचार
17	17	11,14	17-01-2015	लोकमत समाचार
18	18+1	12,16	19-01-2015	लोकमत समाचार
19	19	13	20-01-2015	लोकमत समाचार
20	20	11	21-01-2015	लोकमत समाचार
21	21	13	23-01-2015	लोकमत समाचार
22	22+1	11,14	25-01-2015	लोकमत समाचार
23	23+1	12,14	29-01-2015	लोकमत समाचार
24	24	11	30-01-2015	लोकमत समाचार
25	25+1	13,16	31-01-2015	लोकमत समाचार
26	26			
27	27			
28	28			
29	29			**Total- 40**
30	31			
31	**Total-40**			

संदर्भ सूची

पुस्तकें

1 सिंह अजय कुमार, मीडिया इतिहास और हाशिए के लोग. हरियाणा:अधार प्रकाशन पंचकूला-134 113, 2007

2 जोशी रामशरण, मीडिया-विमर्श.नई दिल्ली:सामयिक प्रकाशन 3320-21 जटवाड़ा,नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, - 110002

3 कुमार संजय, मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओगे.नई दिल्ली: प्रकाशक सम्यक प्रकाशन 32-3, पश्चिमपुरी, 110063,

4 सुमन हंसराज, मीडिया और दलित.नई दिल्ली:प्रकाशन श्री नटराज प्रकाशन 4378/4 बी, 306,जे एन.डी, हाऊस, अंसारी रोड,दरियागंज,110002, 2009

5 फैसल हरिवंश, जन सरोकार की पत्रकारिता.नई दिल्ली:अनुरागप्रकाशन 4715/21 दयानंद मार्ग, दरियागंज, 110002, 2009

6 नैमिशराय मोहनदास, दलित पत्रकारिता.नई दिल्ली:प्रकाशन श्री नटराज ए 507/12 करतार नगर, बाबा श्यामगिरी मार्ग 110053, 2008

7 गौतम रूपचन्द्र, दलित रिपोर्टिंग.दिल्ली: प्रकाशन-ए-507/12, साउथ गांवडी एक्सटेंशन 110053, 2007

8 मल्होत्रा महेन्द्र, मीडिया के सामाजिक,राजनीतिक एवं आर्थिक सरोकार. नई दिल्ली:प्रकाशन-रावत 4264/3, अंसारी रोड, दरियागंज -110002, 2012

9 परिहार डॉ.एस.एल, दलितों को अनपढ़ रखने की साजिश.जयपुर:प्रकाशन-बुद्धम् पब्लिशर्स 21-ए, धर्मपार्क,श्याम नगर11 अजमेर रोड़ -302019 राजस्थान, 2014

10 परिहार कालूराम, मीडिया के सामाजिक सरोकार.नई दिल्ली:प्रकाशन अनामिका प्रब्लिशर्स एंडडिस्ट्री ब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड अंसारी रोड़ दरियागंज110002,2008

11काजल डॉ.अजमे सिंह, दलित चिंतन के आयाम.दिल्ली:प्रकाशन ए-507/12 साउथ गामड़ी एक्स 110053, 2012

12 टाकभौर डॉ.सुशीला, हाशिए का विमर्श. दिल्ली: नेहा प्रकाशन 295, बैंक इक्लेब, लक्ष्मी नगर 110092, 2015

13 सिंह डॉ.राम गोपाल, सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष. जयपुर प्रकाशन राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी प्लाट न. 1 झालाना सांस्थानिक क्षेत्र-302004, 2010

14 भारती कंबल, माझी जनता दलित पत्रकारिता और विमर्श. नई दिल्ली: स्वराज प्रकाशन 7/14 गुप्ता लेन अंसारी रोड दरियागंज 110002, 2011

15 डॉ. मीणा राम लखन, मीडिया विमर्श आधुनिक संदर्भ. दिल्ली: कल्पना प्रकाशन बी 1770 जहांगीरपुरी नजदीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 110033, 2012

16 पचौरी सुधीर, नया मीडिया और नये मुद्दे. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन 21 ए दरियागंज 10002, 2009

17 बेचैन श्यौराज सिहं, अम्बेडकर गांधी और दलित पत्रकारिता.नई दिल्ली: अनामिका प्रा. लिमिटेड 4697/3.21ए अंसारी रोड दरियागंज 110002, 2010

पत्रिकाएं

1 वंचित जनता, जुलाई 2015

2 जन मीडिया, जनवरी 2015

3 फारवर्ड , अक्टूबर 2015

4 दलित विमर्श, सितम्बर 2015

वेब साइट

1 https://hi.wikipedia.org/wiki/सामाजिक संरचना

2 http://www.rachanakar.org/2015/01/blog-post_21.html **देवेंद्र चौबे का आलेख**

3 http://www.rachanakar.org/2015/01/blog-post_21.html

4 http://www.rachanakar.org/2015/01/blog-post_21.html

5 http://www.bbc.com/hindi/regionalnews/story/2006/12/061205_dalit_special_lokhande.shtml

6 http://humsamvet.org.in/1sep2014/11.html
7 http://www.dw.com/hi मीडिया का आईना दिखाते दलित पत्रकार
8 http://zidagikantonbhari.blogspot.in/2009/06/blog-post 22.html